सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 01, नई दिल्ली । गुरुवार, 14 मार्च 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है।

03 असली शीशियों में कैंसर की नकली दवा
06 उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सचेत होने की जरूरत
08 भीलवाड़ा विधायक कोठारी ने जिला कारागृह का किया औचक निरीक्षण

परिवहन विभाग दिल्ली द्वारा आज तक व्यवसायिक पंजीकृत तय समय सीमा समाप्त कर चुके वाहनों की एनओसी का आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नही की, आखिर क्यों?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद काफ़ी समय लगाकर तय समय सीमा समाप्त कर चुके वाहनों के लिए एस.ओ.पी. तो लागू कर दी पर यह एस.ओ.पी. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालय की नजर में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए घोषित की गई लग रही है क्योंकि इस को घोषित करने के बाद भी दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनो जो अपनी निर्धारित तय समय सीमा समाप्त कर चुके हैं के लिए अभी भी एनओसी को अप्लाई करने का आनलाइन / ऑफलाइन कोई भी आवेदन प्रक्रिया शुरू नही की है। **जब वाहन मालिक एनओसी अप्लाई ही नहीं कर सकता तो एनओसी प्राप्त कैसे करेगा, है ना बड़ा सवाल ?** ऐसा नहीं की इसकी जानकारी परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की जानकारी में नही है पर शायद आज की तारीख में दिल्ली परिवहन विभाग में कार्यरत आला अधिकारी के मन मे कुछ और जुबान पर कुछ ही देखने को मिल रहा है। **यहां हम आपकी जानकारी हेतु बताना आवश्यक समझते हैं कि व्यवसायिक पंजीकृत वाहनों की निर्धारित तय समय सीमा समाप्त होने के साथ ही फिटनेस भी समाप्त हो जाती हैं और बिना वैलिड फिटनेस के व्यवसायिक वाहन मालिक अपने वाहन का ना तो परमिट जमा करवा सकता है** और ना ही एनओसी के लिए आवेदन अप्लाई कर सकता है पिछले साल तक दिल्ली परिवहन विभाग व्यवसायिक वाहन मालिकों को जीरो फिटनेस (जिसका प्रयोग वाहन मालिक एनओसी प्राप्त करने के लिए करता था) प्रदान करता था पर आज की तारीख में कार्यरत आला अधिकारी द्वारा ही बंद करवा दी गई थी जिस कारण व्यवसायिक वाहन मालिक एनओसी प्राप्त नही कर पा रहे थे।

एस.ओ.पी. जारी होने के बाद व्यवसायिक वाहन मालिकों को खुशी मिली थीं कि अब वह आराम से एनओसी प्राप्त कर वाहनों को दूसरे राज्यों में ले जा सकेंगे पर परिवहन विभाग के आला अधिकारी शायद दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों को परेशान देखने में ही प्रसन्नता प्राप्त करते हैं जिसका एक उदाहरण कल के समाचार पत्र में सबूत के साथ हमने आपको प्रस्तुत किया था और आज यह भी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत।

मेट्रो के लिए निविदाएं आमंत्रित

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: भुवनेश्वर में मेट्रो ट्रेनों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। यह टेंडर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बुलाया है । पहले चरण में भुवनेश्वर एयरपोर्ट से आचार्य बिहार तक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा । इसके लिए 630 करोड़ 65 लाख रुपये की अनुमानित लागत का अनुमान लगाया गया है ।जबकि 6 स्टेशन बनाए जाने हैं, 3 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है । हालांकि खबर है कि टेंडर के लिए प्री-बिड मीटिंग 19 तारीख को होगी ।

नए डिजाइन के मुताबिक फ्लाईओवर सड़क से करीब 8 मीटर (करीब 26.24 फीट) ऊपर होगा। इस पर मेट्रो चलेगी । मेट्रो रेल ट्रैक जमीन से 14 मीटर (करीब 46 फीट) ऊपर होगा। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए मेट्रो के लिए डीपीआईईआर तैयार किया गया है। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से कटक के त्रिशुल्वे चाचा तक 26 किमी लंबे मेट्रो रेल ट्रैक के लिए डेपियर तैयार किया गया है।

दूसरी ओर, मेट्रो परियोजना के पहले चरण में हवाई अड्डे से कैपिटल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन भवन स्ट्रीट, बापूजीनगर, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, राम मंदिर स्ट्रीट, वालाबिहार, आचार्यबिहार स्ट्रीट, जयदेवबिहार, जेवियर स्ट्रीट, रेलवे सदन, ड्रैस्टिक सेंटर, दमना शामिल होंगे। स्ट्रीट, पाटिया स्ट्रीट, कीथ स्ट्रीट, नंदन बिहार।, रघुनाथपुर, नंदनकानन चिड़ियाघर, फुलपोखरी से गुजरते हुए त्रिशुवंजा चाचा तक पहुंचते हैं। भुवनेश्वर हवाई अड्डे से कटक त्रिशुवाला तक 26 किलोमीटर की मेट्रो लाइन ज्यादातर मध्य रेखा पर बनाई जाएगी। निर्माण प्रीकास्ट तकनीक से किया जाएगा।

ढेंकनाल स्टेशन पर यात्रियों की दुर्दशा

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: ढेंकनाल स्टेशन पर यात्रियों की दुर्दशा । स्टेशन पर न तो पानी की व्यवस्था है और न ही अच्छे शौचालय। रेलवे अधिकारी I/W को जिम्मेदारी दी गई है लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पंखे की भी व्यवस्था नहीं है । ठेकेदार काम कर रहा है, उसे पानी दिया जा रहा है या फिर यात्रियों को पीने के लिए पानी नहीं है । उच्च अधिकारियों को पता चला है कि प्लेटफार्म नंबर 2 पर आने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए यात्रियों को परेशान किया जा रहा है ।प्रतिदिन सैकड़ों यात्री सफर कर रहे हैं, रेलवे विभाग करोड़ों का राजस्व कमा रहा है या यात्री परेशान हैं ।लागत बढ़ रही है, लेकिन ढेंकनाल में अब पानी

उपलब्ध नहीं है ।यात्रियों ने रेल मंत्री अश्विन बिष्णुब से मांग की है कि इसे ठीक किया जाए ।

फोरलेन कार्य की निितिन गडकरी से की ऑनलाइन शिकायत

कोटला (कांगड़ा)। पठानकोट-मंडी फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर कंपनी के विरुद्ध केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से ऑनलाइन शिकायत भेजने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत भाली के निवासी अमन राणा ने यह शिकायत की है। उनका कहना है कि कंपनी के अधिकारियों की ओर से आम जनता की समस्याओं की सुनवाई ही नहीं की जा रही है, निपटारा करना तो बड़ी दूर की बात है। निर्माण कार्य के दौरान धूल मिट्टी बड़ी मात्रा में हवा में फैल रही है। उन्होंने आरोप लगाए कि भाली के साथ लगते 35 मील क्षेत्र में कंपनी की ओर से पहले पहाड़ी में मिट्टी का मलबा फेंका। उसी कच्चे मलबे पर बहुत बड़े बड़े दो डंगों का निर्माण नियमों के विरुद्ध कर दिया। उधर, फोरलेन निर्माण कंपनी के अधिकारी राजीव नैयर का कहना है कि भाली में दो टैंकर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जबकि जो डंगे लगाए गए हैं, वह विशेषज्ञ तकनीकी टीम की जांच के बाद ही लगाए गए हैं।

क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से भारत देश प्रदुषण मुक्त हो जाएगा क्या इसका लिखित आश्वासन भारत देश में उपस्थिति राजनैतिक दल, राजनेता जनता को दे सकते हैं ?

भारत सरकार और राज्य सरकारें क्यों नहीं भारत में ही उपल्ब्ध एल्यूमीनियम और सोडियम टेक्नोलॉजी के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग में लाने के लिए बैट्री उत्पादन पर अपना बल और सहयोग प्रदान करे।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत देश को प्रदुषण मुक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय सरकारों द्वारा जो जनता को बताया और दिया गया है वह है **इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग। क्या इलेक्ट्रिक वाहनों को अन्य फ्यूल मोड के वाहनों की जगह प्रयोग करने से भारत देश प्रदुषण मुक्त हो जाएगा इसका लिखित आश्वासन भारत देश में उपस्थिति राजनैतिक दल, राजनेता जनता को दे सकते हैं ?** यह आश्वसन इस लिए भी जरुरी है क्योंकि प्रदुषण के लिए वाहनों के अलावा भी बहुत अन्य कारण और कारक है जिन पर सरकार/ राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है।

आप सब की जानकारी हेतु बताना चाहता हूं की आज के युग में प्रयोग में आने वाले मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयोग करने के लिए जिस लिथियम बैट्री की आवश्यकता बनाई गई है उसके स्वरूप को लिथियम के कच्चे माल से प्रयोग युक्त बनाने वाला देश आज की तारीख में सिर्फ चीन है और भारत देश में जब तक इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम बैट्री का प्रयोग किया जाने की बात कही जाती रहेंगी तब तक इलेक्ट्रिक वाहन जनता की पहुंच से बहुत दूर रहेगा और फायदा ना चाहते हुए भी चीन को पहुंचेगा। भारत सरकार और राज्य सरकारें क्यों नहीं भारत में ही उपल्ब्ध एल्यूमीनियम और सोडियम टेक्नोलॉजी के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग में लाने के लिए बैट्री उत्पादन पर अपना बल और सहयोग प्रदान करे। एल्यूमिनिम और सोडियम टेक्नोलॉजी वाली भारत में उपल्ब्ध कच्चे माल से निर्मित बैट्रीया लिथियम से बेहतर और सस्ती पड़ेगी और साथ ही देश का पैसा ना सिर्फ देश के विकास और प्रगति के काम आएगा अपितु इस तकनीक की बनी बैट्री का एक्सपोर्ट भी भरपूर मात्रा होगा और भारत का नाम।

NHAI ने Paytm FASTag यूजर्स को फिर चेताया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। NHAI ने एक बार फिर Paytm FASTag यूजर्स को चेताया है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को सुविधाजनक ट्रैवल एक्सपीरिएंस बनाए रखने के लिए 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक से नया फास्टैग प्राप्त करने की सलाह दी है।

NHAI ने अब क्या कह दिया ?

NHAI द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय जुर्माने या दोहरे शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से संबंधित प्रतिबंधों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के बाद, पेटीएम फास्टैग यूजर्स के पास 15 मार्च,2024 के बाद अपने बैलेंस को रिचार्ज या टॉप-अप करने का विकल्प नहीं होगा।

Paytm FASTag का 15 मार्च के बाद क्या होगा ?

Paytm FASTag यूजर निर्धारित तिथि के बाद भी टोल का भुगतान करने के लिए मौजूदा शेष राशि का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। NHAI ने Paytm FASTag यूजर्स को अपने संबंधित बैंकों तक पहुंचने या IHMCL (इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) की वेबसाइट पर दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखने की सलाह दी।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

अब 10 गुना जुर्माना पूरे देश एवं प्रदेश के अंदर ट्रैफिक के हो चुके हैं इसलिए सभी ट्रैफिक के नियमों की पालना अबश्य करे

नेशनल रोड सेफ्टी सप्ताह 2024 के अंर्न्तगत रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन ने सड़क सुरक्षा पर विशेष अभियान चलाया

परिवहन विशेष न्यूज

पलवल। जिला पलवल रोड सेफ्टी कॉउन्सिल की चेयरमैन एवं डिप्टी कमिश्नर जिला पलवल नेहा सिंह आईएएस के आदेशानुसार एवं शशि वशुंदरा HCS डीटीओ जिला पलवल के निर्देशानुसार एवं सरदार देवेंदर सिंह सदस्य स्टेट रोड सेफ्टी कॉउन्सिल हरियाणा सरकार के मार्गदर्शन में आज नेशनल रोड सेफ्टी सप्ताह 2024 के अंर्न्तगत रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) ने जी डी एस डी कॉलेज, पलवल के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा पर विशेष अभियान चलाया गया जिसमें सभी कॉलेज के बच्चों को मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बारे में बताया गया कि अब 10 गुना जुर्माना पूरे देश एवं प्रदेश के अंदर ट्रैफिक के हो चुके हैं इसलिए सभी ट्रैफिक के नियमों की पालना अबश्य करे जैसे स्कूटी एवं बाइक चलाते समय ISI मार्क हेलमेट

ही पहनना, हमेशा ही ट्रैफिक लाइट पर ही रुकना, हमेशा ही ज़ेबरा क्रॉसिंग पर रुकना, और रेड लाइट जंप बिलकुल नहीं करनी, उलटी दिशा में वाहन को बिलकुल नहीं चलाना और हमेशा कार चलाते समय अपनी सीट बेल्ट पहनना जरूरी है ।अपनी अपनी गाड़ी स्पीड लिमिट में ही चलाये नशा करके गाड़ी बिलकुल ना चलाये अपनी अपनी गाड़ी के पेपर अपने साथ रखे किरपा पैदल चलने वालो को पहले रास्ता अबश्य दे आजकल CCTV के माध्यम से भी चालान घर पर भेजे जा रहे है हमेशा सड़क पर एम्बुलेंस को रास्ता पहले दे अगर आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम को अगर आप हॉस्पिटल ले जाते है आपको पुलिस तंग नहीं करेगी क्युकी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स है आपको पुलिस सम्मानित भी कर सकती है गुड समार्टियन अवार्ड दे कर इसलिए आप सड़क पर अगर कही एक्सीडेंट होता है तो आप अपना पूरा सहयोग अबश्य करे आप सभी हमेशा पुलिस एवं प्रशासन को सहयोग करें जिससे सडक दुर्घटनाओं में ज्यादा से ज्यादा कमी लाई जा सके। महाविद्यालय कि सड़क सुरक्षा समिति इंचार्ज डा जितेंद्र ने सभी कॉलेज के छात्र-छात्राओं को शपथ दिलाई कि वे सडक सुरक्षा नियमों की पालना करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डा पूनम पाहुजा, डा हरदीप सिंह नरवाल एवं श्री परवीन कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। महाविद्यालय प्राचार्य डा नरेश कुमार ने सभी विद्यार्थिओं के सुरक्षित एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। आप सभी का जीवन बहुत ही अनमोल है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा

हेलमेट पुलिस को देखकर नहीं अपने परिवार को देखकर

असुरक्षित हो गईं बेटियां, कब रुकेंगे अत्याचार

विश्व गुरु कहलाने वाले भारत में महिलाओं पर जुल्मों की सूची लंबी होती जा रही है। देश की राष्ट्रीय राजधानी ही सुरक्षित नहीं है'

देश में बेटियां हर जगह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बेटियों की सुरक्षा के दावे कहां हैं, यह एक यक्ष प्रश्न है। यह सुलगता प्रश्न है कि बेटियां कब सुरक्षित होंगी। हाल में एक घटनाक्रम वाराणसी में घटित हुआ है जहां बीएचयू परिसर में कुछ गुंडों द्वारा एक लडक़ी के साथ अश्लील हरकतें करने और वीडियो बनाने की घटना सामने आई है। साल के 365 दिनों में महिलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाओं पर अनगिनत अत्याचार हो रहे हैं, मगर सरकारों की कुंभकरणी नींद नहीं टूट रही है। आज कोई भी विश्वास के योग्य नहीं रहा है, किस पर विश्वास करें, अपने ही हैवान बन रहे हैं। आज बाबुल की गलियां ही नरक बन गई हैं। अपने रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बहू-बेटियां घर में ही असुरक्षित हैं। समय-समय पर ऐसे घिनौने कर्म होते हैं कि कायनात कांप उठती है कि आदमी इतने नीच काम क्यों कर रहा है। महिलाएं कहीं भी महफूज नहीं हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में प्रतिदिन घटित वारदातों से महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगता जा रहा है। इन वारदातों से हर भारतीय उद्वेलित है। सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे, तभी इन पर रोक लग सकती है। जघन्य व दिल दहला देने वाली दुष्कर्म की घटनाओं से जनमानस खौफजदा है। आखिर कब तक बेटियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। ऐसी वारदातें बहुत ही चिंतनीय हैं। दरिंदे बेखौफ होकर अराजकता फैला रहे हैं।

दरिंदों की दरिंदगी की वारदातें कब रुकेंगी, कोई पता नहीं। अपराध की तारीख बदल जाती है, मगर तस्वीर नहीं बदलती। बेशक प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, मगर ऐसे आयोजन केवल मात्र औपचारिकता भर रह गए हैं, क्योंकि हर वर्ष एक संकल्प लिया जाता है कि महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जाएगी, अत्याचारों का खात्मा किया जाएगा, सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, मगर धरातल की सच्चाइयां बेहद ही खौफनाक तस्वीरें प्रस्तुत कर रही हैं। आधी दुनिया पर बढ़ते अत्याचार देश के लिए अशुभ संकेत है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता की बुलंदियां छू रही हैं। चांद तक अपनी काबीलियत का परचम फहरा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सैकड़ों कड़े कानून बनाए गए हैं, मगर ये कानून सरकारी फाइलों की धूल चाट रहे हैं। अगर कानून सही तरीके से लागू किए होते तो इन मामलों में इजाफा नहीं होता। आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे घर हो, दफ्तर हो, बस, सडक़, गली या चौराहा हो, महिलाएं हर जगह असुरक्षित ही महसूस कर रही हैं। वर्ष 2019, 2020, 2021 व 2022 में भी दरिंदों ने दरिंदगी जारी रखी। वर्ष 2023 में भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 12 सितंबर 2018 को हरियाणा के रेवाड़ी में 19 साल की एक मेधावी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 27 जून 2018 को मध्यप्रदेश के मंदसौर में सात साल की नाबालिग स्कूली बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य घटना से हर भारतीय उद्वेलित हुआ था। यह बच्ची तीसरी में पढ़ती थी। मासूम से हुई दरिंदगी व हैवानियत की यह घटना बहुत ही दिल दहलाने वाली थी। दरिंदों ने जिस बर्बरता व हैवानियत से घटना को अंजाम दिया था, उससे रौंगटे खड़े हो जाते हैं। दरिंदों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी थी। कानून को धता बताकर दरिंदे दरिंदगी का तांडव कर रहे हैं। दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ कर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। अब समय आ गया है कि दरिंदों को फांसी की सजा से ही इन मामलों पर विराम लग सकता है। वर्ष 2023 के जनवरी माह से देश के हर राज्य में इन मामलों में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। साल के हर माह में ये दुष्कर्म रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार को इन मामलों पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी।

कुछ समय पहले कठुआ में भी एक बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला प्रकाश में आया था। प्रतिदिन इन अपराधों में इजाफा होता जा रहा है। हिमाचल में भी गुडिया कांड हुआ था। इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाला कृत्य हुआ था जब द्वारकानाथ इलाके में देर रात टैक्सी से घर लौट रही एक महिला से रेप का मामला घटित हो गया था। देश में लड़कियां कितनी महफूज हैं, इन घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है। 26 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसी वारदातें खौफनाक हैं। रेप व हत्या की ऐसी घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं। देश में हर रोज अबोध बच्चियों से लेकर अधेड़ उम्र की महिलाओं तक से दुष्कर्म हो रहे हैं। फांसी की सजा से ही इन मामलों पर विराम लग सकता है। बीते वर्ष 2022 में भी अत्याचारों का सिलसिला बेखौफ चलता रहा। हजारों महिलाएं व नाबालिग बच्चियां दुष्कर्मों का शिकार हुईं। वर्ष 2023 के प्रथम माह जनवरी से ही महिलाओं पर अत्याचारों की शुरुआत हो चुकी है। जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक में देश में हजारों घटनाएं घटित हो चुकी हैं। प्रतिदिन ऐसे मामले हो रहे हैं और निरंतर इन मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। छेड़छाड़ के अलावा तेजाब फेंकने व दुष्कर्म की घटनाएं भी बदस्तूर जारी हैं। वर्ष 2019 में एक खौफनाक व दरिंदगी की हदें पार करने वाला घटनाक्रम पंजाब के मोगा में हुआ था, जब बदमाशों ने चलती बस में लडक़ी से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर बस से फैंक दिया, जिस कारण उस लडक़ी की मौत हो गई थी। गत वर्ष उत्तर प्रदेश का बदायूं एक बार फिर शर्मसार हुआ था जहां एक बार फिर दो नाबालिग चचेरी बहनों से गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया था। पांच आरोपियों ने शौच को गई नाबालिगों को अगवा करके उनके साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया था। आज बाल विवाह हो रहे हैं। नाबालिग लड़कियों की शादियां अधेड़ों से की जा रही हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध समाज को कार्रवाई करनी चाहिए। 16 दिसंबर 2012 को जो हादसा दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था, उसके बाद देश में महिलाओं से होने वाले दुष्कर्मों की बाढ़ सी आ गई कि हर दिन राजधानी से लेकर शहर व गांवों में सामूहिक दुष्कर्म थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज हर जगह दुशासन महिलाओं की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। विश्व गुरु कहलाने वाले भारत में महिलाओं पर जुल्मों की सूची लंबी होती जा रही है। जब देश की राष्ट्रीय राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो महानगरों व छोटे कस्बों का क्या हाल होगा?

महिला कृपया ध्यान दें, 5 संकेतों से समझ जाए खून की हो गई है भारी कमी, तुरंत करें सुधार वरना संकट आएगा हजार

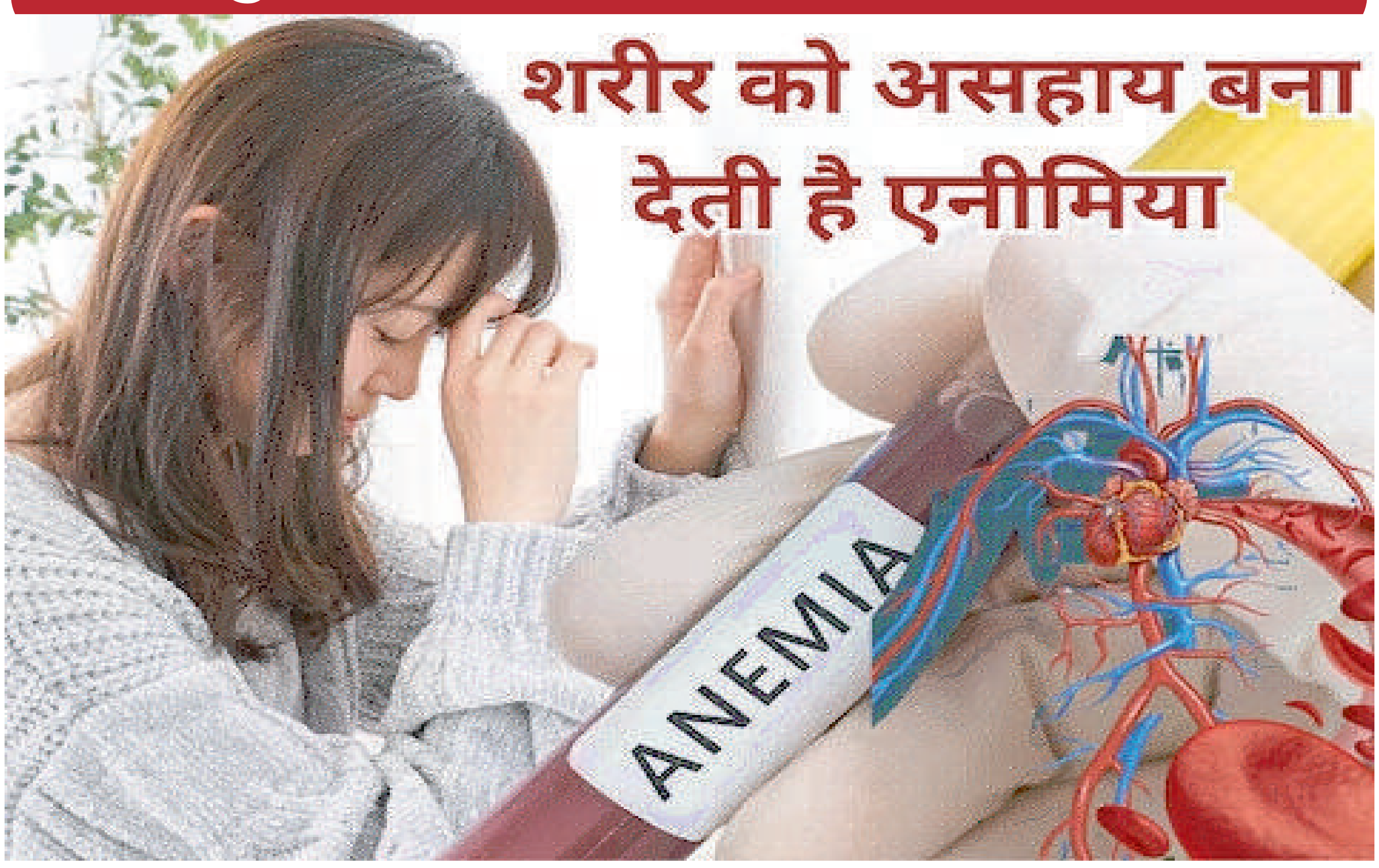

महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक खून की कमी रहती है, लेकिन अगर इस कमी को दूर नहीं किया जाए तो इसके शरीर में कई खतरनाक परिणाम दिख सकते हैं.

प्रकृति ने महिलाओं के शरीर को नायाब तरीके से रचा है. लेकिन इस नायाबपन के कारण महिलाओं का शरीर पुरुष की तुलना में ज्यादा जटिल होता है. यही कारण है महिलाओं को खून की ज्यादा जरूरत होती है. चूंकि खून सबके लिए जीवन का आधार है. इसलिए खून की कमी का घातक असर होना लाजिमी है. खून ही शरीर के हर एक अंग से दूसरे अंगों का संपर्क संभव बनाता है. खून के कारण ही शरीर के अंग-अंग में ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों की पहुंच होती है और वहां से कार्बनडायऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना होता है. इसलिए शरीर के प्रत्येक अंग में खून का पहुंचना जरूरी है. खून के आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन शरीर के अंग-अंग तक पहुंचती है. हीमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन का पहुंचना कम हो जाता है.

जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसे एनीमिया की बीमारी होती है. महिलाएं अक्सर एनीमिया की शिकार हो जाती हैं. लेकिन अगर एनीमिया का इलाज जल्दी नहीं किया गया तो महिलाओं का शरीर इतना लुंज-पुंज हो जाता है कि कुछ भी काम सही से नहीं हो पाता है. महिलाओं के शरीर में कुछ खास संकेत एनीमिया के लक्षण की ओर इशारा करते हैं.

महिलाओं को खून की कमी क्यों होती है ज्यादा

मायो क्लिनिक के मुताबिक जब भोजन में आयरन की मात्रा ज्यादा न हो या किसी न किसी वजह से ज्यादा खून शरीर से निकल रहा हो तो एनीमिया की बीमारी हो सकती है. वहीं कुछ बीमारियों के कारण भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है. रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में हर महीने पीरियड्स के दौरान खून बाहर निकलता है. जिन महिलाओं को हैवी पीरियड्स होते हैं, उनमें एनीमिया का रिस्क ज्यादा रहता है. दूसरी ओर अगर भोजन में हरी पत्तीदार सब्जियों की कमी होती है तो भी एनीमिया की बीमारी हो सकती है. इस तरह महिलाएं हमेशा एनीमिया की रिस्क में रहती हैं.

आयरन की कमी के संकेत

1. बहुत अधिक थकान और कमजोर- जब महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तब सबसे अधिक शरीर में कमजोरी और थकान होती है. इतनी कमजोरी हो जाती है कि कुछ काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि ऑक्सीजन हर अंग तक नहीं पहुंचती. इससे नसें शिथिल होने लगती है जिससे शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होती है.

2. भूख नहीं लगना-एनीमिया की बीमारी होने पर महिलाओं में भूख बहुत कम लगती है. ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है. चूंकि पहले से कमजोरी और थकान रहती ही है, ऐसे में अगर पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं.

3. सिर दर्द और चक्कर- अगर महिलाओं में एनीमिया हो जाए तो अक्सर सिर में दर्द और चक्कर की शिकायत रहती है. इससे पूरा दिन खींझ रहती है. कोई काम करने में बेचैनी होने लगती है.

4. स्किन के रंग में बदलाव- एनीमिया या शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर स्किन का रंग पीला पड़ने लगता है. नाखून बहुत कमजोर होने लगते हैं. हाथ-पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं.

5. छाती में दर्द- हीमोग्लोबिन की कमी होने पर सांसें तेज चलने लगती है. इसका कारण है कि हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है इसलिए कभी-कभी दम भी फूलने लगता है. इससे छाती में भी दर्द हो सकता है.

कैसे खून की कमी को करें पूरा

आयरन की कमी के लिए नॉन वेजिटेरियन सीफूड, मीट, ड्राई फ्रूट आदि का सेवन करें. वहीं जो लोग वेजिटेरियन हैं या नहीं भी हैं वे, ड्राई फ्रूट, डार्क ग्रीन पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक, केले आदि का सेवन करें. किशमिश, खुबानी, ही मटर, फूलगोभी, चकोतरा, संतरा, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, अनार आदि फ्रूट जल्दी से आयरन की कमी को पूरा कर देंगे.

यंग भारतीय लड़कियों पर तेजी से अटैक कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर! रिपोर्ट में सामने आए डरावने तथ्य

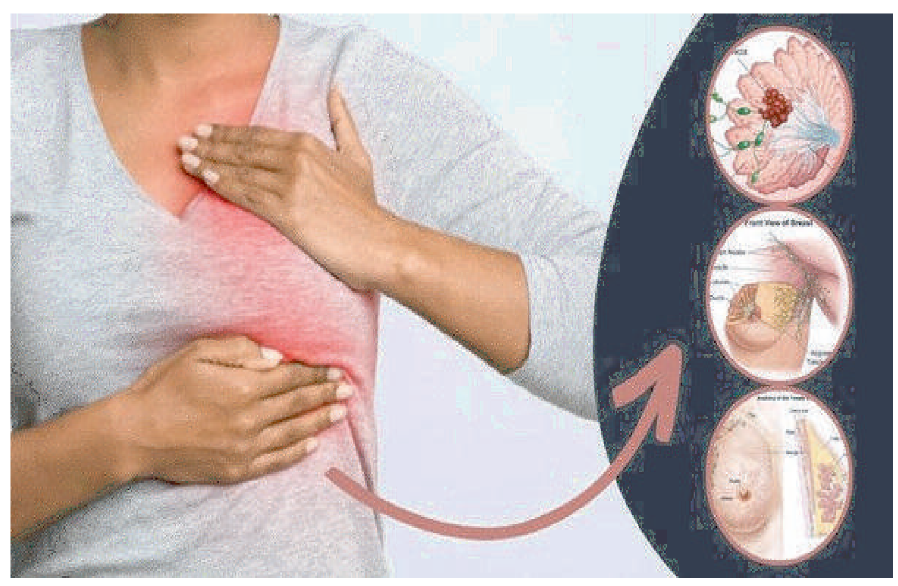

भारत में स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है और उसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि यह युवा महिलाओं को ज्यादा चपेट में ले रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, 20-40 साल की युवा महिलाओं में स्तन कैंसर के केस अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से सामने आ रहे हैं...

दुनिया भर में जिस कैंसर से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, वही कैंसर अब भारत में पहले से कहीं अधिक तेजी से पांव पसार रहा है. भारतीय महिलाओं, खासतौर से युवा लड़कियों और महिलाओं में, ब्रेस्ट कैंसर (स्तर कैंसर) के केस ज्यादा देखे जा रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि 20 से 40 साल की युवा महिलाओं में स्तन कैंसर की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, स्तन कैंसर दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाला सबसे आम प्रकार का कैंसर है. साल 2020 में 20 लाख से ज्यादा महिलाओं में स्तन कैंसर का पता चला और 6 लाख से अधिक मरीजों की जान चली गई. ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस (Breast Cancer Awareness) को लेकर हो रहे तमाम सम्मेलनों और रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं.

ब्रेस्ट कैंसर के क्या हैं शुरुआती लक्षण

स्तन कैंसर जागरूकता पर हाल ही में एक वेबिनार के दौरान फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल की मेडिकल ऑन्कोलॉजी की वरिष्ठ सलाहकार डॉ सफलता बाघमार ने कहा, 'स्तन कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाले सबसे आम प्रकार के कैंसर के रूप में हेल्थ चार्ट में सबसे ऊपर है और हाल के दिनों में इसकी घटनाएं बढ़ी हैं. समय पर निदान और प्रभावी उपचार के लिए स्तन कैंसर के शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है. नई गांठें, स्तन की बनावट में बदलाव, त्वचा की अनियमितताएं, निपल से जुड़ी समस्याएं, निपल से खून आने जैसे बदलावों पर नजर रखना बेहद जरूरी है.'

डॉक्टर बाघमार ने कहा, 'इस बारे में खास बात यह भी याद रखनी चाहिए कि ये लक्षण जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, वे गैर-कैंसरजन्य बीमारियों या कंडिशन्स से भी जुड़े हो सकते हैं. इसलिए, जब संदेह हो, तो जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि यह आखिर क्या है और सही इलाज करवाना चाहिए. वैसे मन की शांति के लिए भी बेहतर है कि पेशेवर मार्गदर्शन लें.' (यह भी पढ़ें– स्तन कैंसर से बचने के लिए 40 की उम्र के बाद जरूर कराएं स्क्रीनिंग)

नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार, 'भारत में स्तन कैंसर महिलाओं में कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है. 2020 में, भारत में दो लाख से अधिक महिलाओं में स्तन कैंसर का इलाज होने का अनुमान लगाया गया था और अनुमान के अनुसार 76,000 से अधिक मौतें हुईं.' इसी रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में यह संख्या बढ़कर 2.3 लाख से अधिक होने की संभावना है.

गुरुग्राम के सीके बिड़ला अस्पताल में ऑन्कोलॉजी के प्रमुख सलाहकार और स्तन केंद्र के प्रमुख डॉ. रोहन खंडेलवाल ने बताया, 'भारत में, स्तन कैंसर की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से 20 के दशक के अंत और 30 के दशक की शुरुआत में युवा भारतीय महिलाओं में.

साल 2030 तक स्तन कैंसर दोगुना!

भारत में, स्तन कैंसर सर्वाइकल (cervical cancer) और ओरल कैविटी कैंसर (Oral Cavity Cancer) को पीछे छोड़ते हुए सबसे आम कैंसर और कैंसर से संबंधित मौतों का प्रमुख कारण बन गया है. अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 2030 तक स्तन कैंसर के केस दोगुना होने की संभावना है. 20 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोग का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए नियमित स्तन जांच कराने की सलाह दी जाती है."

डॉक्टरों के अनुसार, स्तन कैंसर के 60 प्रतिशत मामलों का निदान आमतौर पर एडवांस स्टेज में किया जाता है, जिससे इलाज की दर कम हो जाती है. फिर भी, नियमित जांच से इलाज की दर 80-90 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.

स्तन कैंसर को लेकर कौन से टेस्ट कब करवाएं

कोच्चि के अमृता अस्पताल में रेडियोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी आर ने कहा कि किशोरों और 20 से 30 वर्ष की आयु के लोगों के लिए, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सबसे पहले करवाया जा सकता है, इसके बाद अगर आवश्यक हो तो मैमोग्राफी की जाती है।

दिल्ली की सभी 7 सीटों पर BJP उम्मीदवार घोषित, 3 पूर्व महापौर पर भाजपा ने जताया भरोसा

ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने से पहले पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने राजनीतिक से संन्यास का एलान कर दिया था। इस बार भाजपा ने नई दिल्ली सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है।

परिवहन विशेष न्यूज

बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में भाजपा ने 72 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम एलान किया है। इससे पहले भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इस बार भाजपा ने नया दांव चलते हुए दिल्ली में छह सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं।

नई दिल्ली। भाजपा ने दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में दिल्ली की पांच सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे। वहीं, बुधवार को आई भाजपा की दूसरी लिस्ट में दो और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है।

3 पूर्व महापौर को टिकट

इस बार भाजपा ने मनोज तिवारी को छोड़कर दिल्ली की बाकी सभी सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि भाजपा की ओर से दिल्ली में तीन पूर्व महापौर को चुनावी मैदान में उतारा गया। योगेंद्र चांदोलिया एकीकृत निगम में जहां स्थायी समिति के चेयरमैन रहे हैं तो वह एकीकरण से पहले उत्तरी निगम में महापौर भी रहे हैं।

इसी तरह पूर्वी निगम के पूर्व महापौर हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से टिकट दे दिया है। इससे पहले भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची में पश्चिमी दिल्ली से पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत को चुनावी मैदान में उतारा हैं। योंग्रेंद्र चांदोलिया वैसे तो मध्य दिल्ली के करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई है। वह निगम में दो बार चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं। योगेंद्र चांदोलिया 56 वर्ष के हैं।

गौतम गंभीर का राजनीति से संन्यास

ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने से पहले पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने राजनीतिक से संन्यास का एलान कर दिया था। इस बार भाजपा ने नई दिल्ली सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है।

किस सीट पर कौन उम्मीदवार

चांदनी चौक- प्रवीण खंडेलवाल
नई दिल्ली- बांसुरी स्वराज
उत्तर पूर्वी दिल्ली- मनोज तिवारी
दक्षिणी दिल्ली- रामवीर सिंह बिधूड़ी
पश्चिमी दिल्ली- कमजीत सेहरावत
पूर्वी दिल्ली- हर्ष मल्होत्रा
उत्तर पश्चिमी दिल्ली- योगेंद्र चांदोलिया

दिल्ली-NCR में बदला मौसम, गाजियाबाद-नोएडा में बूंदाबांदी शुरू; चल रही ठंडी हवाएं

राजधानी दिल्ली सहित आसपास के शहरों में बुधवार को मौसम ने करवटी दी है। दोपहर को बादल छाने से मौसम सुहावना हो गया है। हवा चलने से दिन में जो धूप निकलते समय गरमाहट बनी हुई थी वो सर्द हो गई है। मौसम विभाग ने भी दो-तीन घंटे में बारिश की संभावना बताई है। दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही बनी हुई है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित आसपास के शहरों में बुधवार को मौसम ने करवटी दी है। दोपहर को बादल छाने से मौसम सुहावना हो गया है। शाम होते-होते गाजियाबाद और नोएडा में बूंदाबांदी शुरू हो गई। सर्द हवा चलने से थोड़ी सी ठंड का अहसास हुआ है।

दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही सुबह से बनी हुई है। कभी बादल तो कभी धूप का सिलसिला चल रहा है। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने बताया कि बादलों की आवाजाही की वजह पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है।

हरियाणा से दिल्ली की ओर बादलों की आवाजाही

मौसम विभाग के अनुसार, रडार पर दक्षिण हरियाणा से दिल्ली की ओर बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। अगले दो-तीन घंटों में दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम दिल्ली में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

यहां बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 घंटों के दौरान हरियाणा के गोहाना, महम, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहेल, फारुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, बावल, औरंगाबाद, होडल और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा राजस्थान के भिवाड़ी, तिजारा, कोटपुतली, अलवर में हवाएं चलेंगी।

दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, 48 घंटे में सुलझाई बाइक सवार से लूट की गुत्थी; दो पकड़े

दिल्ली पुलिस ने बाइक पर जा रहे युवक के साथ लूट की घटना का 48 घंटे के अंदर गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने आसपास लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दो आरोपितों को पहचाना। इसके बाद कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान नदीम व दूसरे की पहचान खुरसीद के रूप में हुई है।

बाहरी दिल्ली। एक युवक से मोबाइल व पर्स लूटने वाले दो बदमाश को जहांगीरपुरी पुलिस ने 48 घंटे के भीतर दबोच लिया है। इसके पास से पुलिस ने लूटा गया मोबाइल व पर्स बरामद कर लिया । इसके अलावा एक चोरी का मोबाइल फोन व स्कूटी भी बरामद की है। दोनों आरोपित आदतन और सक्रिय अपराधी हैं। **चाकू दिखाते हुए की लूट :** उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीते 9 मार्च को की रात 11:30 बजे शिकायतकर्ता सोनू ने पुलिस को बताया कि वह मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे, जब वह मुकुंदपुर चौक के पास पहुंचे, पीछे से आए स्कूटी सवार दो व्यक्ति ने उसे रोक लिया।

सर्दियों में टॉप-10 प्रदूषित शहरों में दिल्ली और चंडीगढ़ शीर्ष पर रहे; ये शहर भी रहे शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

सर्दियों में दिल्ली और चंडीगढ़ देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहे। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वॉयरमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें एक अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक देश के 36 में से 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विश्लेषण किया गया। इसमें कहा गया कि दिल्ली और चंडीगढ़ सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहे। टॉप 10 शहरों में बिहार और उत्तर प्रदेश भी शामिल रहे।

नई दिल्ली। सर्दियों के प्रदूषण पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के नए विश्लेषण में दिल्ली और चंडीगढ़ इस बार सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहे हैं। शीर्ष 10 में बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं बंगाल भी शामिल हैं।

सीएसई ने एक अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक देश के 36 में से 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विश्लेषण किया है। यहां के 254 शहरों के 538 एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों से पीएम 2.5 के आंकड़े लिए गए। सात राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मानिटरिंग ही नहीं हो रही। ज्ञात हो कि पीएम 2.5 का सामान्य स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।

क्षेत्रीय स्तर पर बनाई जानी चाहिए कार्ययोजना

सीएसई के अर्बन लैब प्रमुख अविकल सोमवंशी ने बताया कि प्रदूषण बढ़ने की वजह स्थानीय कारकों के साथ हवा की मंद गति और वर्षा कम होना रही। स्थिति में सुधार के लिए सीएसई ने सुझाव भी दिए हैं। कहा गया है कि शहर पर केंद्रित करने के बजाए प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना क्षेत्रीय स्तर पर बनाई जानी चाहिए। साथ ही एनसीआर की तरह अन्य शहरों में भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) सरीखी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

विश्लेषण में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

पश्चिमी हिमालय : जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड
उत्तर भारत : चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
पूर्वी भारत : बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
मध्य भारत : छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
पश्चिम भारत : गुजरात, महाराष्ट्र
दक्षिण भारत : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना
पूर्वोत्तर भारत : असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा

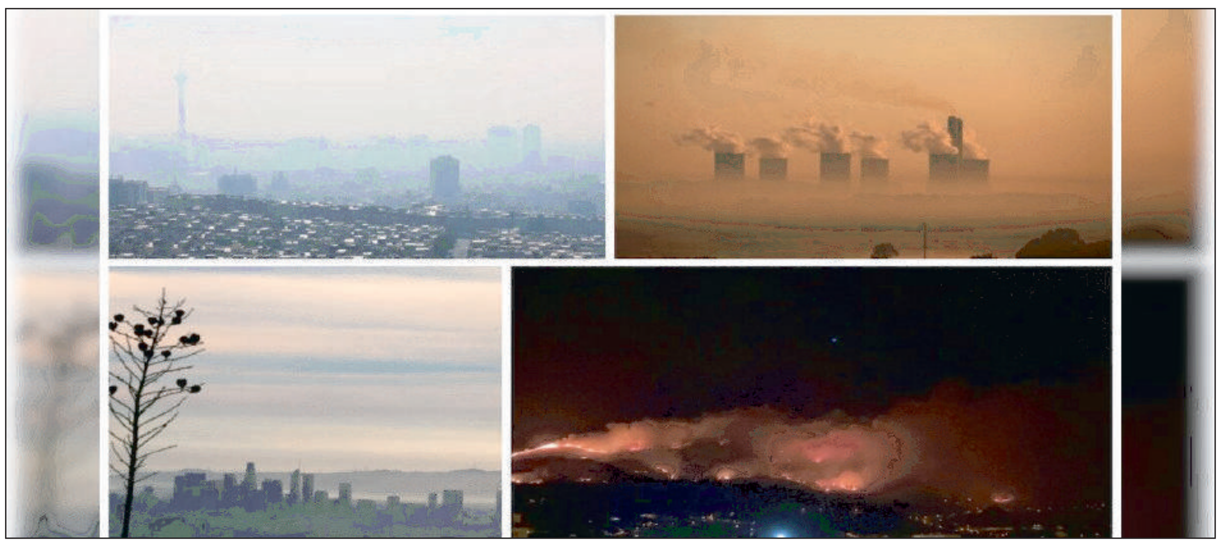

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं मिले प्रदूषण के आंकड़े

दादर नागर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश

सर्वाधिक प्रदूषित शीर्ष 10 शहर

सर्दियों के दौरान पीएम 2.5 का औसत और चरम स्तर (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में)

शहर	औसत स्तर	चरम स्तर
दिल्ली	188	364
चंडीगढ़	100.9	283
बिहार	98.3	174
हरियाणा	96.4	210
उत्तर प्रदेश	87.8	174
राजस्थान	85.6	152
पंजाब	78.3	164
ओडिशा	78.0	149
असम	71.9	133
बंगाल	66.7	114

वायरल वीडियो के चर्चा में आने की वजह बने पीएम मोदी, जिसे देख प्रधानमंत्री भी हुए गदगद

परिवहन विशेष न्यूज

सोशल साइट एक्स पर एक वीडियो चर्चा में है जिसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह वीडियो दिल्ली के पास के शहर का है। वीडियो को देख पीएम मोदी काफी खुश हुए। उन्होंने अपना रिएक्शन एक्स पर लिखा। इस वीडियो पर कई सारे कमेंट भी आ रहे हैं। यह वीडियो नमो भारत ट्रेन का है जो गाजियाबाद जिले में दुहाई से साहिबाबाद के बीच चलती है।

नई दिल्ली। सोशल साइट एक्स पर एक वीडियो चर्चा में है, जिसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह वीडियो दिल्ली के पास के शहर का है। वीडियो को देख पीएम मोदी काफी खुश हुए। उन्होंने अपना रिएक्शन एक्स पर लिखा। इस वीडियो पर कई सारे कमेंट भी आ रहे हैं। यह वीडियो नमो भारत ट्रेन का है, जो गाजियाबाद जिले में दुहाई से साहिबाबाद के बीच चलती है। पीएम मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया था। यह ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी। फिलहाल कॉरिडोर के निर्माण का कार्य अभी किया जा रहा है।

एक्स पर मोहित कुमार नाम से अकाउंट द्वारा वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें नमो भारत ट्रेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को पार कर रही है। कैप्शन में इसे अद्भुत दृश्य बताया गया है।

पीएम मोदी ने इस वीडियो को री-पोस्ट किया है और केप्शन में लिखा, करते हुए, ग्रेट वीडियो... आपकी टाइमलाइन उस नए भारत का एक अच्छा परिप्रेक्ष्य देती है, जिसका हम साथ मिलकर निर्माण कर रहे हैं।

12वीं पास युवक फर्जी वीजा बनाकर लोगों को भेजता था विदेश, पुलिस ने एजेंट को दबोचा

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया जो लोगों को फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने का काम करता था। पकड़ा गया एजेंट मात्र 12वीं पास है। पुलिस सूचना के आधार पर पंजाब गई और स्थानीय मुखबिर की मदद से उसे धर दबोचा। वह अमृतसर में मेसर्स ग्लोबल वीजा साल्यूशन नाम की कंपनी चलाकर लोगों से ठगी करता था।

नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने कम दामों में फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने का लालच देने वाले एक एजेंट को पकड़ा है। आरोपित ने फर्जी वीजा लगाकर यात्री को पांच बार अमेरिका भेजने का प्रयास किया, लेकिन चेकिंग के दौरान उन्हें वापस लौटा दिया गया।

आरोपित सुल्तान सिंह पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यात्री फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कजाकिस्तान से दिल्ली की यात्रा करने वाले गुरप्रीत सिंह को एयरपोर्ट से आठ मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपित से पूछताछ की। जिसमें उसने बताया कि काम के सिलसिले में वह अमेरिका जाना चाहता था।

इसको लेकर वह गांव के निवासी सुल्तान सिंह नाम के एक एजेंट के संपर्क में आया। अमेरिका भेजने के नाम पर सुल्तान ने उससे 10 लाख रुपए ले लिए। फिर पुलिस आरोपित सुल्तान को पकड़ने के लिए जांच तेज कर दी। पुलिस सूचना के आधार पर पंजाब गई और स्थानीय मुखबिर की मदद से उसे धर दबोचा। आरोपित 12वीं तक ही पढ़ा है। वह अमृतसर में मेसर्स ग्लोबल वीजा साल्यूशन नाम की कंपनी चलाकर लोगों से ठगी करता था।

आरोपित सुल्तान सिंह पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यात्री फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कजाकिस्तान से दिल्ली की यात्रा करने वाले गुरप्रीत सिंह को एयरपोर्ट से आठ मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपित से पूछताछ की। जिसमें उसने बताया कि काम के सिलसिले में वह अमेरिका जाना चाहता था।

असली शीशियों में कैंसर की नकली दवा, IIT BHU से बीटेक कर चुका युवक था सप्लायर; दिल्ली से पुणे तक चल रहा था मौत का खेल

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। कीमोथेरेफी की नकली दवाओं का कारोबार करने के आरोप में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस इससे पहले सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आठवें आरोपी की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी आदित्य कृष्णा के तौर पर हुई है। उसे दिल्ली लाया गया है।

आदित्य कृष्णा नीरज चौहान से दवाईयां खरीदता था और उसे पुणे और एनसीआर में सप्लाई करता था। वह मुजफ्फरपुर में दवाई की दुकान चलाता था। वह आईआईटी बीएचयू से बीटेक कर चुका है। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में ले जाया जाएगा।

सस्ती कीमत पर दवा मुहैया कराने का झांसा

गिरफ्तार आरोपितों में दो दिल्ली के रोहिणी स्थित नामी राजीव गांधी कैंसर अस्पताल के कर्मचारी है। आरोपित इस कैंसर अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले कीमोथेरेपी में इस्तेमाल इंजेक्शनों की खाली शीशियां प्राप्त कर उसमें एंटी फंगल दवा भरकर दिल्ली, हरियाणा व बिहार समेत अन्य राज्यों के दवा विक्रेताओं व कैंसर के मरीजों से सीधे संपर्क कर उन्हें सस्ती कीमत में दवा मुहैया करने का झांसा देकर बेच देते थे।

नेपाल और अफ्रीकी देशों के लोगों को बनाते थे शिकार

ये लोग खासतौर पर नेपाल और अफ्रीकी देशों से कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली आने वाले मरीजों को शिकार बनाते थे। कीमोथेरेपी की दवाईयां बहुत हार्ड होती हैं, जिसके इस्तेमाल से बाल भी झड़ जाते हैं। ये दवाई बहुत महंगी आती हैं, लेकिन आरोपितों द्वारा बेची जाने वाली नकली दवाओं में कोई भी ऐसा सॉल्ट नहीं होता है जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल पाए।

दिल्ली के मोती नगर में बनाई जाती थी नकली दवाएं

गिरफ्तार आरोपित बिना किसी सक्रिय घटक के नकली दवाएं उपलब्ध कराकर झूठी उम्मीदें

बेचता था और मरीजों के बहुमूल्य जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। नकली दवाइयां दिल्ली के मोती नगर में बनाई जाती थी। आरोपितों की निशानदेही पर सात अंतरराष्ट्रीय व दो भारतीय ब्रांडों की चार करोड़ रुपये मूल्य की नकली कैंसर की दवाएं बरामद की गई हैं।

बुंदेलखंड के बाद पश्चिमी यूपी के इस जिले में 'जल संकट', भूजल स्तर नीचे गिरने से रेड जोन घोषित

बुंदेलखंड के पांच जिलों में भूजल स्तर नीचे गिरने के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले में जलसंकट की स्थिति पैदा हो गई है। जिले में लगातार भूजल स्तर गिरता ही जा रहा है। इसके लिए प्रमुख सचिव भी चिंता जता चुके हैं। भूगर्भ जल विभाग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अनियंत्रित दोहन से...

गाजियाबाद। जिले में भूजल स्तर दिनोंदिन नीचे जा रहा है। गाजियाबाद को रेड जोन घोषित किया जा चुका है। बुंदेलखंड के पांच जिलों महोबा, ललितपुर, झांसी, बांदा और हमीरपुर के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तेजी से गिरते भूजल स्तर गिरने को लेकर प्रमुख सचिव भी चिंता जता चुके हैं। कई औद्योगिक इकाइयों का शुरू हुआ सर्वे तेजी से गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए निर्देश दे चुके हैं। यही वजह रही कि कई-कई वर्षों से धरती का सीना चीरकर अवैध भूजल दोहन कर रहीं 30 हजार से अधिक छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों का जिला भूगर्भ प्रबंधन समिति ने सर्वे जनवरी माह में शुरू किया था, जो लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही थम गया है। गाजियाबाद में पानी के अनियंत्रित दोहन से न सिर्फ जमीनी सतह का जल, बल्कि जमीन के नीचे के जल दोहन खतरे के निशान को पार कर गया है। इसका खुलासा भूगर्भ जल विभाग की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 तक भूगर्भ जलस्तर 24.9 मीटर पर था। वह 2023 में गिरकर 33 मीटर पर पहुंच गया। यानी सात साल में भूगर्भ जल स्तर करीब सात मीटर से भी अधिक गिर गया।

एनसीआर के आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों पर बीजेपी की नजर, सुनील कुमार शर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

साहिबाबाद विधायक सुनील कुमार शर्मा को मंगलवार को इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिलने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा ने इस कदम से आइटी सेक्टर के लोगों को साधने की जुगत लगाई है। गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद गुरुग्राम और फरीदाबाद आइटी हब के रूप में जाने जाते हैं।

आइटी सेक्टर के ज्यादातर लोग हाईराइज सोसायटियों में रहते हैं। पिछले चुनावों के आंकड़ों की बात करें तो हाईराइज सोसायटियों के मतदाताओं का मतदान प्रतिशत काफी कम रहता है। मतदान के दिन होने वाली छुट्टी को वह अवकाश के रूप में मनाते हैं। उन्हें फ्लैटों से निकालने के लिए प्रशासन, सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत अधिक सफल नहीं होते हैं।

साहिबाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए साहिबाबाद विधायक सुनील कुमार शर्मा को मंगलवार को इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिलने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सियासतबाज कहने लगे कि इससे लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आइटी सेक्टर के लोगों को साधने की जुगत लगाई है।

आइटी सेक्टर का हब है एनसीआर

गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद आइटी हब के रूप में जाने जाते हैं। इन शहरों में आइटी सेक्टर से जुड़े लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। सुनील कुमार शर्मा इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं।

इससे इन शहरों के आइटी सेक्टर से जुड़े लोगों की उनसे अपेक्षाएं बढ़ेंगी। उनसे आइटी सेक्टर में और बेहतरी लाने की अपेक्षा करेंगे। राजनीति के जानकारों की मानें तो भाजपा इसे वोट बैंक में बदलने की कोशिश करेगी। यदि भाजपा ऐसा करने में सफल हुई तो पार्टी को काफी फायदा होगा।

हाईराइज सोसायटी में बन सकती है पैठ

आइटी सेक्टर के ज्यादातर लोग हाईराइज सोसायटियों में रहते हैं। पिछले चुनावों के आंकड़ों की बात करें तो हाईराइज सोसायटियों के मतदाताओं का मतदान प्रतिशत काफी कम रहता है। मतदान के दिन होने वाली छुट्टी को वह अवकाश के रूप में मनाते हैं। उन्हें फ्लैटों से निकालने के लिए प्रशासन, सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत अधिक सफल नहीं होते हैं।

सियासतबाजों का कहना है कि सुनील कुमार शर्मा की मदद से भाजपा हाईराइज सोसायटियों में रहने वाले आइटी सेक्टर के लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। उन्हें अपने पक्ष में मतदान के लिए बाहर निकालने की जुगत करेगी। यदि ऐसा करने में भाजपा भाजपा सफल होती है तो गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व दिल्ली में पार्टी को इसका काफी फायदा मिल सकता है।

आइटी नीति के साथ वोट बैंक बढ़ाने का लक्ष्य

प्रदेश सरकार ने आइटी सेक्टर को बढ़ाने के लिए आइटी नीति 2012 लागू की थी। इसका उद्देश्य आइटी हब के रूप में ग्रेटर नोएडा व नोएडा के अनुभवों के लाभ को पूरे प्रदेश में फैलाना था। यह नीति सफल रही है। इसी का परिणाम है कि लखनऊ में पीपीपी माडल पर 100 एकड की आइटी सिटी/आइटी नगर का निर्माण कर उसका विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना है। इस आइटी नगर में न्यूनतम 1,500 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 75 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस नीति के क्रियान्वयन का एक लाभ यह भी है कि आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर व गोरखपुर में आइटी पार्क की स्थापना की प्रक्रिया में आ चुकी है। राजनीति के जानकारों की मानें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा इससे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। सुनील कुमार शर्मा गाजियाबाद के मूल निवासी होने के कारण पार्टी के इस मकसद को पूरा करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इन्हीं सभी समीकरणों की वजह से उन्हें इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिला है।

सड़क सुरक्षा को लेकर डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक के साथ बैठक

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद। दिन वीरबार 14.03.2024 को मैडम उषा देवी HPS डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद के साथ रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) के सदस्यों की सड़क सुरक्षा को लेकर रूम नंबर :603,6th फ्लोर डीसी ऑफिस सेक्टर -12 फरीदाबाद में मीटिंग सड़क सुरक्षा की होने जा रही है समय :11 45 सुबह सेक्टर -29 चौक पर ट्रैफिक लाइट एवं रोड मार्किंग रोड सिग्न जल्द से जल्द लगनी चाहिए एवं अतिक्रमण जल्द से जल्द हटना चाहिए।

1. रोड मार्किंग रोड सिग्न एवं ज़ेबरा क्रासिंग ज्यादातर शहर एवं गांव में आजकल मिसिंग है एवं शहर एवं गांव में वाटर लॉगिन की समस्या ठीक होनी चाहिए
2. शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिलकुल ठीक ठाक एरिया वाइज शहर एवं गांव एवं नेशनल हाईवे पर सुबह एवं नाईट तक ठीक होना चाहिए
3. शहर एवं गांव की सड़के एवं ट्रैफिक लाइट ,CCTV कैमरे ठीक ठाक होनी चहिये
4. शहर के सभी डिपार्टमेंट की जिमेदारी सड़क सुरक्षा एवं नोडल अफसर के लिए तय होनी चाहिए
5. ऑटो का सिस्टम ठीक होना चाहिए ऑटो के ड्राइवर के लिए स्पेशल ड्राइविंग कैंप लगे होने चाहिए ऑटो ,ट्रेक्टर ट्राली की फिटनेस चेक होनी चाहिए
6. इललीगल बस ,मारुती वैन की समस्या का हल होना चाहिए जो इस समय शहर में रोजाना ही इललीगल चल रहे है
7. शहर एवं गांव में नो एंट्री में वाहन ट्रक एवं डम्पर सड़क पर बिलकुल नहीं चलने चाहिए
8. शहर एवं गांव में सड़क पर गाये ,सड़ सड़को पर एवं गालिओ में जगह जगह घूम रहे है जो रोजना एक्सीडेंट का कारन बन रहे है
9. नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग टीम एवं ट्रैफिक पुलिस सुबह एवं लेट नाईट तक अबश्य ही होनी चाहिए
10. ट्रैफिक पुलिस में टेक्निकल विंग बिलकुल होनी चाहिए एक स्पेशल ट्रैफिक नंबर होना चाहिए
11. सभी स्कूल एवं कॉलेज का समय अलग अलग होना चाहिए एवं सभी स्कूल एवं कॉलेज के बाहर इनके सिक्योरिटी गार्ड अबश्य लगे होने चाहिए
12. ट्रैफिक पुलिस की लेटेस्ट ट्रैफिक की टेक्निकल एवं लॉ की ट्रेनिंग अबश्य होनी चाहिए
13. ट्रैफिक पुलिस में चालान काटने की टीम एवं ट्रैफिक चलाने वाली टीम बिलकुल अलग अलग होनी चाहिए
14. ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद का फेसबुक पेज ,इंस्टाग्राम एवं ट्विटर रोजाना एक्टिव होना चाहिए
15. हर जिला फरीदाबाद के चैराहो पर शराब ठेके का जगह जगह होना आसपास अतिक्रमण रेहड़ी का जगह जगह पर होना
16. शहर एवं गांव में सभी डिपार्मेंट सड़क बनाने से पहले पुलिस से NOC अबश्य ही लेनी चाहिए

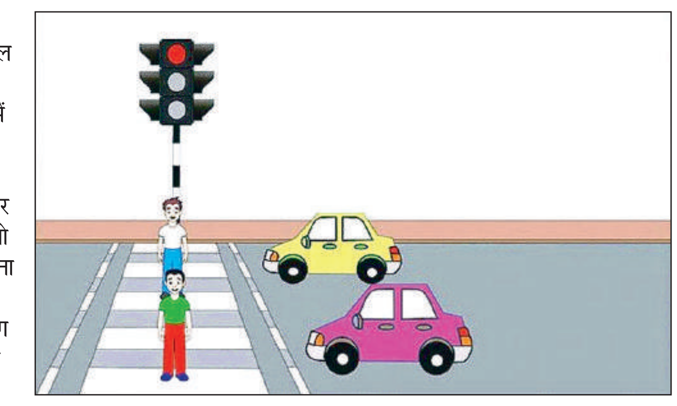

स्पेशल नोट : पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद के ऑफिस के बाहर पिछले 10 सालो से ज्यादा वाटर लॉगिन होता है एवं पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद के कट पर लेफ्ट मुड़ने पर अतिक्रमण का एवं पेड़ का ठीक ना होना चाहिए इसी तरह फरीदाबाद में सभी जगह समस्या है एवं पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद के घर के सामने एशियाई हॉस्पिटल के द्वारा स्मार्ट सिटी की सड़क पर एवं सेक्टर 21 A जगह पर अवैध पार्किंग एवं ट्रैफिक बूथ के आसपास अतिक्रमण होना

नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड पर रोजाना अतिक्रमण का होना इसके लिए फरीदाबाद जिले के लिए एक मजिस्ट्रेट अबश्य होना चाहिए

शहर एवं ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर भी सड़क के हर चोरोहे पर जगह जगह अतिक्रमण का होना एवं सभी बाजारों में जगह जगह अतिक्रमण का होना

अगर किसी को कोई समस्या हो आप इस मोबाइल नंबर पर अबश्य बात करे

प्रदीप मल्लाह
पैट्रन रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.)
मोबाइल नंबर :9312208722
रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.)

इमरजेंसी नंबर :

विवेक चंडोक
सीनियर वाईस प्रेजिडेंट रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.)
मोबाइल नंबर :9540966667

बलजीत सिंह सैनी
डायरेक्टर ट्रेनिंग एवं ऑपरेशन रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.)
मोबाइल नंबर :7550505085

जिला MMG अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर मनोज कुमार चतुर्वेदी का हुआ तबादला, आदेश जारी

गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर मनोज कुमार चतुर्वेदी का तबादला हो गया है। शासन स्तर से जारी आदेश के अनुसार उनकी तैनाती वरिष्ठ परामर्शदाता के तौर पर जिला अस्पताल सहारनपुर में की गई है। वह दो साल से एमएमजी में कार्यरत थे। डॉक्टर मनोज कुमार चतुर्वेदी के तबादले के बाद जिला अस्पताल में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर मनोज कुमार चतुर्वेदी का तबादला हो गया है। शासन स्तर से जारी आदेश के अनुसार उनकी तैनाती वरिष्ठ परामर्शदाता के तौर पर जिला अस्पताल सहारनपुर में की गई है। वह दो साल से एमएमजी में कार्यरत थे।

ओपीडी में बढ़ी बुखार के मरीजों की संख्या

जिला एमएमजी अस्पताल और संयुक्त अस्पताल की ओपीडी में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मंगलवार को दोनों अस्पतालों में पहुंचे तीन हजार मरीजों में बुखार के 856 मरीज पहुंचे। सीएमएस डॉ. मनोज कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि एमएमजी में बुखार के 344 मरीज और खांसी-जुकाम के 451 मरीज पहुंचे। इनमें बीमार बच्चों की संख्या 260 रही। संयुक्त अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे 1001 मरीजों में बुखार के 331, खांसी-जुकाम के 210 और बीमार बच्चे 107 पहुंचे। महिला अस्पताल में भी बुखार के मरीजों की संख्या अधिक रही।

77 की जांच में तीन लोग संक्रमित मिले

सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में पहुंचे 77 मरीजों की जांच करने पर एक बुजुर्ग समेत तीन लोग संक्रमित मिले हैं। सेवानगर के रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग, मिसलगढ़ी की महिला और नंदग्राम की युवती के संक्रमित मिलने पर होमआइसोलेशन में इलाज शुरू कर दिया गया है। सीएमओ डा.भवतोष शंखधर ने बताया कि वर्तमान में कोरोना के नौ सक्रिय मरीज हैं। इनमें से आठ का इलाज होमआइसोलेशन में चल रहा है। एक अस्पताल में भर्ती हैं।

दूसरे दिन भी टीबी के मरीजों की नहीं हुई ऑनलाइन रिपोर्ट

प्रदेश स्तर से संविदाकर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही है। एसोसिएशन के जिला मंत्री चंद्रप्रकाश ने बताया कि दो दिवसीय डिजिटल हड़ताल के दौरान टीबी की जांच रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई। इसके चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। उधर सीएमओ ने टीबी विभाग का आकस्मिक निरीक्षण करने पर अनुपस्थित मिले आठ से अधिक कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश जारी किए हैं।

राजनीति के अपराधीकरण का सशक्त उदाहरण है शाहजहां शेख का मामला

उमेश चतुर्वेदी

ऐसे अपराधियों की शह गाहे-बगाहे ममता द्वारा उठाए गए कदमों से भी मिली। कुछ साल पहले ममता बनर्जी ने अपने ही एक पुलिस अधिकारी के बचाव में धरने पर बैठ गई थीं। तब सीबीआई ने उस अधिकारी के घर छापा मारा था।

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का आरोपी शाहजहां शेख 29 फरवरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी के बाद संदेशखाली में जश्न का माहौल होना स्वाभाविक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शाहजहां शेख पर जब आरोप लगे, तभी उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही उसे गिरफ्तार क्यों किया गया ? उसकी गिरफ्तारी के संदर्भ में गौर करने की एक बात और है कि उसकी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस ने तब की है, जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि शाहजहां शेख की गिफ्तारी सीबीआई या बंगाल पुलिस या फिर कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कर सकती है।

हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद तय हो गया कि शाहजहां शेख को अब गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। तब पश्चिम बंगाल की सरकार को लगा कि अगर केंद्रीय एजेंसियां उसे पकड़ती हैं तो लोकसभा चुनावों के ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस की स्थिति कमजोर होगी। भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करने का मौका मिलेगा और फिर चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। इसी वजह से शाहजहां शेख को उसी संदेशखाली से पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां उसके न होने की बात कही जा रही थी। कहा तो यहां तक जा रहा था कि शेख पश्चिम बंगाल से लंदन भागने की फिराक में है।

शाहजहां शेख का नाम राशन घोटाले में छापा मारने गई प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के बाद ज्यादा चर्चा में आया। जबकि उसका आपराधिक साम्राज्य पहले से ही चल रहा था। उसके आपराधिक साम्राज्य और राज्य की सत्ताधारी राजनीति में उसकी दखल और दबंगई का अंदाजा इस बात से लगाया ज सकता है कि ईडी की टीम पर उसके गुंडों ने उसकी शह पर हमला किया। ईडी के अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं। इसके बावजूद वह फरार रहा। पश्चिम बंगाल की सरकार उसे गिरफ्तार करने की जहमत तक नहीं उठा रही थी। ऐसे में 29 फरवरी की उसकी गिरफ्तारी भी सवालों के घेरे में रखी जा सकती है। यह मानने के लिए कोई संदेह नहीं है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का एक तरह से रस्म पूरा किया है। ताकि आशंकित राजनीतिक नुकसान से बचा जा सके।

शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल के सत्ता के दुरुपयोग का अनूठा केस है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के ठीक 55 दिनों बाद उसकी गिरफ्तारी होना एक तरह से पश्चिम बंगाल की सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। दिलचस्प यह है कि साल 2011 में ममता बनर्जी जिन मूल्यों को स्थापित करने के लिए माटी और मानुष का नारा देकर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थीं, वे मूल्य उनकी सत्ता ने कभी अख्तियार ही नहीं किए। सत्ता में आने के पहले तक ममता ने तत्कालीन वाममोर्चा सरकार की जमकर बखिया उधेड़ी। उन्होंने वाममोर्चा सरकार को अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और महिलाओं की इज्जत तार-तार करने वाली सत्ता साबित करने में कामयाब रहीं। ऐसे में उम्मीद थी कि जब वे सत्ता में आएंगी, पश्चिम बंगाल की स्थितियां बदलेंगी। वहां अमन-चैन कायम होगा। महिलाओं की अस्मिता की रक्षा होगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के रवैये में बहुत बदलाव नहीं हुआ। दरअसल हुआ यह कि पहले जो वामपंथी दलों के साथ कैडर के रूप में स्थानीय आपराधिक तत्व जुड़े हुए थे, अपने स्थानीय हितों के लिए वे तृणमूल कांग्रेस के साथ आते चले गए। फिर मौका देखते ही उन्होंने अपने पुराने ढर्रे को अपना लिया। तृणमूल के नेता भी आर्थिक अपराधों में शामिल होते चले गए। नौकरी के लिए घोटाला हो, या फिर शारदा घोटाला या कुछ और, तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपने-अपने ढंग से भ्रष्टाचार में शामिल होते चले गए। इसका असर यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में सत्ता भले ही बदल गई, सत्ता का चरित्र नहीं बदला।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने से पहले ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री रहीं। वे सदा साधारण सूती साड़ी पहनती रहीं, हवाई चप्पल और पुरानी फिएट कार से चलती रहीं। उन्होंने अपने पुराने कालीघाट के घर में ही रहना जारी रखा। ऐसे में उनसे उम्मीद थी कि वे सत्ता में भ्रष्टाचार को काबू करेंगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उलटा। वाममोर्चे के दौरान के असामाजिक टाइप के तत्व बदली हुई सत्ता के साथ तालमेल करने में कामयाब रहे और उन्होंने तृणमूल में भी पैठ बना ली। यही वजह है कि शाहजहां शेख जैसे गलीछाप अपराधी देखते ही देखते ताकतवर बनकर उभर जाते हैं। उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वे खुलेआम जमीनें कब्जियातें हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। और तो और केंद्रीय एजेंसियों तक पर खुलेआम हमला कर देते हैं।

ऐसे अपराधियों की शह गाहे-बगाहे ममता द्वारा उठाए गए कदमों से भी मिली। कुछ साल पहले ममता बनर्जी ने अपने ही एक पुलिस अधिकारी के बचाव में धरने पर बैठ गई थीं। तब सीबीआई ने उस अधिकारी के घर छापा मारा था। जब कोई मुख्यमंत्री पहले से ही मान लेता है कि उसका कार्यकर्ता या अधिकारी सही है, ईमानदार है। और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ वही खुद मोर्चा खोल देता है तो जाहिर है कि राज्य के दूसरे ऐसे तत्वों को भी शह मिलती है और वे आगे आकर केंद्रीय एजेंसियों को ना सिर्फ चुनौती देते हैं, बल्कि वे राजनीति शह भी हासिल करते हैं। इसके बाद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं रह जाता। फिर सत्ता और राजनीति के संरक्षण से ऐसे अपराधी खुलेआम अपराध करते हैं।

लेकिन शाहजहां शेख के मामले में जिस तरह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीके आनंद बोस और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है, उसी वजह से उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। उसे तृणमूल कांग्रेस ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि मतता का यह कदम लंबे समय तक के लिए रहेगा या फिर सिर्फ चुनावों के दौरान की किरकिरी से बचने की कवायद है ? अब तक तृणमूल का जो इतिहास रहा है, उससे तो नहीं लगता कि शाहजहां शेख के मामले में पार्टी कोई सबक लेने जा रही है और आने वाले दिनों में वह राजनीति में शुचिता को बढ़ावा देने के लिए आगे आएगी। दरअसल पांच जनवरी को ईडी की टीम ने राज्य के राशन घोटाले में शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा था। उसी दौरान अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई।

जिसके पीछे शाहजहां शेख और उसके समर्थकों का हाथ बताया गया। तब से शाहजहां शेख फरार था। खुद पर हमले के बाद ईडी ने एफआईआर दर्ज कराई, फिर सीबीआई ने शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। उसकी फरारी के करीब महीने भर बाद स्थानीय महिलाओं ने शेख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। संदेशखाली में 8 फरवरी से महिलाएं शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ सड़कों पर उतर गईं। महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां और उसके समर्थकों ने उनका यौन शोषण किया है और उनकी जमीनें जबरन कब्जा कर ली हैं। महिलाओं ने स्थानीय टीएमसी नेता उत्तम सरदार और शिबप्रसाद हाजरा पर भी ऐसे ही आरोप लगाए। जो शाहजहां शेख के करीबी माने जाते हैं। इसके अगले यानी नौ फरवरी को शाहजहां समर्थक हाजरा के तीन पोल्ट्री फार्मों प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जला दिया। महिलाओं का दावा है कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन पर बने हैं। इसके अगले दिन यानी 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार को इस घटना पर त्वरित और प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए सरकार से कहा। बोस ने महिलाओं को राजभवन में संरक्षण देने का भी प्रस्ताव दिया। इस बीच बंगाल राज्य की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। 12 फरवरी को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस वार्ता की। इसके साथ ही संदेशखाली की घटना बंगाल की न होकर देशभर में चर्चा का विषय बन गई। तब से लेकर अब तक राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, फैक्ट फाइंडिंग टीम ने तनावग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। बहरहाल अब मामला हाईकोर्ट की निगरानी में है। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि 42 मामले हैं, अब कोर्ट के चक्कर काटो। हाईकोर्ट के कड़े रूख से उम्मीद तो बनी है। लेकिन देखना यह होगा कि आगामी चुनावों में यह मुद्दा किसके लिए मुफीद हो पाता है और किसके लिए घाटे का कारण।

Maruti eVX टेस्टिंग के दौरान फिर आई नजर, कई डिटेल्स आई सामने; जानिए लॉन्च टाइमलाइन

Maruti eVX टेस्टिंग के दौरान फिर आई नजर आई है। नए स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि eVX के फ्रंट लेफ्ट फेंडर पर एक चार्जिंग पोर्ट होगा। ये चार्जिंग पोर्ट को सामने लगाने की तुलना में बेहतर जगह लगती है जो असेसबिलिटी फैक्टर को बढ़ाती है लेकिन सामने से टकराव होने पर ये असुरक्षित हो सकती है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। Maruti Suzuki अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार में लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रही है। eVX के नए टेस्टिंग म्यूल को हाल में फिर से टेस्ट करते हुए देखा गया है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

Maruti Suzuki eVX की डिजाइन

नए स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि eVX के फ्रंट लेफ्ट फेंडर पर एक चार्जिंग पोर्ट होगा। ये चार्जिंग पोर्ट को सामने लगाने की तुलना में बेहतर जगह लगती है, जो असेसबिलिटी फैक्टर को बढ़ाती है, लेकिन सामने से टकराव होने पर ये असुरक्षित हो सकती है।

दिख रहा है कि फ्रंट और रियरव्यू मिरर पर कैमरे लगे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक एसयूवी में 360-डिग्री कैमरा होगा। सामने की ओर हेडलैम्प्स हैं, जो प्रोडक्शन-स्पेक लगते हैं। इसमें कोई फ्रंट ग्रिल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक एयर डैम है, जो संभवतः इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को ठंडा करने के लिए है।

इसे मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा एसयूवी को थ्री-डोर और अधिक स्ट्रीम-लाइन लुक देने के लिए पीछे के दरवाजे के हैंडल को सी-पिलर पर रखा गया है। इसे एक शार्क-फिन एंटीना, हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप और रियर स्पॉइलर ऑफर किया जा सकता है। इसके अलावा उम्मीद है कि इसमें लाइट बार भी ऑफर किया जाएगा।

फीचर्स और इंटीरियर

फीचर्स के मामले में उम्मीद है कि Maruti Suzuki eVX वायरलेस चार्जर, फ्रंट-वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और एक ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम के साथ आएगी। इसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी हो सकता है, जो एंड्रॉइड ऑटो के साथ-साथ एपल कारप्ले को भी सपोर्ट करेगा।

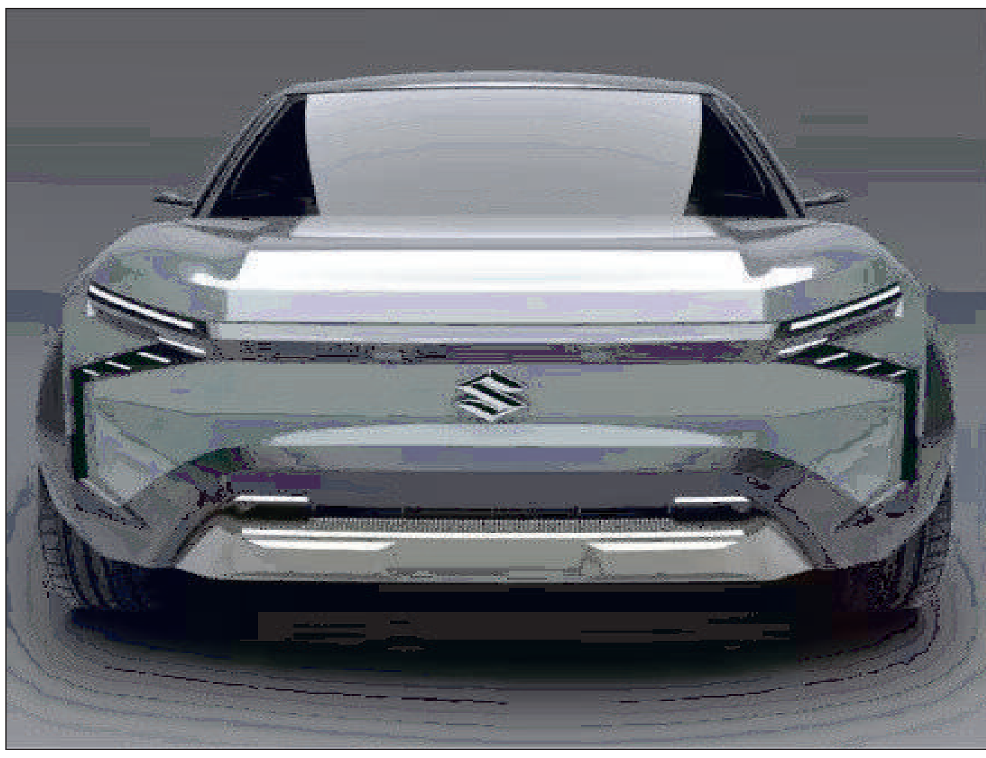

400 से 500 सीसी सेगमेंट में किन बाइक्स की रही मांग, फरवरी 2024 में किसकी कैसी रही बिक्री, जानें डिटेल

भारत में बड़े इंजन और फीचर्स के साथ आने वाली बाइक्स को काफी पसंद किया जाता है। पिछले कुछ समय से 400 से 500 सीसी सेगमेंट में कई कंपनियों की ओर से बाइक्स को पेश किया गया है। बीते महीने में 400 से 500 सीसी सेगमेंट की किस बाइक की बाजार में सबसे ज्यादा मांग रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से फरवरी 2024 के दौरान देश में वाहनों की बिक्री की रिपोर्ट को जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 400 से 500 सीसी के सेगमेंट में किस कंपनी ने किस बाइक की बिक्री की है। हम इस खबर में आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं।

Bike Sales In February 2024

भारतीय बाजार में लगातार वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है। सामान्य फीचर्स और कम कीमत के साथ ही ज्यादा फीचर्स और महंगी बाइक्स को भी देश में काफी पसंद किया जा रहा है। सियाम की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 के दौरान देशभर में 400 से 500 सीसी सेगमेंट के वाहनों की कुल बिक्री 7843 यूनिट्स रही है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में इस सेगमेंट में 4193 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

नंबर-1 पर रही Bajaj

देश की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो की ओर से इस सेगमेंट में कई विकल्प उपलब्ध करवाए जाते हैं। कंपनी की ओर से 400 से 500 सीसी सेगमेंट में डोमिनार के साथ ही केटीएम, हस्कवर्ना और ट्रॉयम्फ की बाइक भी बिक्री के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं। फरवरी 2024 में इन बाइक्स की कुल बिक्री 3233 यूनिट्स रही है। जबकि पिछले साल फरवरी महीने में कंपनी ने 1330 यूनिट्स की बिक्री की थी।

दूसरे नंबर पर Royal Enfield

बुलेट बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड की ओर से भी 400 से 500 सीसी सेगमेंट में हिमालयन को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस बाइक को फरवरी 2024 में 2278 ग्राहकों ने खरीदा। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने पिछले साल 2841 यूनिट्स की बिक्री की थी।

Hero Motocorp की भी रही मांग

हीरो मोटोकॉर्प की ओर से भी इस सेगमेंट में एक्स440 हॉर्ले डेविडसन को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस बाइक की बीते महीने में 2219 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कंपनी की ओर से इस बाइक को पिछले साल ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। इस बाइक को हीरो मोटोकॉर्प और हॉर्ले डेविडसन ने मिलकर बनाया है।

Honda और Kawasaki की भी हुई बिक्री

होंडा की ओर से इस सेगमेंट में सीबी500 को ऑफर किया जाता है। सियाम की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने फरवरी 2024 के दौरान सीबी500 बाइक की 66 यूनिट्स की बिक्री की है। वहीं कावासाकी मोटर्स की ओर से एलिमिनेटर, केएलएक्स450आर और केएक्स 450 बाइक्स की 42 यूनिट्स की बिक्री की गई है।

Jeep SUV: अमेरिकी कंपनी JEEP भारत में लाएगी नई SUV, Creta से लेकर Vitara को मिलेगी टक्कर

अमेरिका की वाहन निर्माता Jeep की ओर से भारतीय बाजार में जल्द ही नई SUV को लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी Hyundai Creta Kia Seltos Maruti Grand Vitara जैसी SUV को टक्कर लेने के लिए नई Compact SUV को लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की ओर से इसे कब लाया जाएगा और किन फीचर्स के साथ यह आएगी। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका की एसयूवी बनाने वाली कंपनी Jeep भारतीय बाजार में एक और SUV को लाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक कंपनी अपनी नई एसयूवी को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ला सकती है। जिससे हुंडई, किआ, मारुति, टोयोटा जैसी कंपनियों को कड़ी चुनौती मिल पाएगी। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी की ओर से नई एसयूवी को किन फीचर्स के साथ लाया जा सकता है।

Jeep लाएगी नई SUV

एसयूवी बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जीप भारत में जल्द ही नई एसयूवी को लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की योजना सबसे सस्ती एसयूवी को भारत में लाने की है। जिससे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मौजूद अन्य वाहनों को कड़ी चुनौती मिल पाएगी।

कैसे होंगे फीचर्स

JEEP की नई SUV को सिट्रॉएन की सी3 एयरक्रॉस के प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें कंपनी की ओर से सिग्नेचर स्टाइल वाली ग्रिल और लाइट्स को दिया जा सकता है। नई एसयूवी में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स के साथ ही इंडिकेटर माउंटिड ओआरवीएम, रूफ रेल, एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो, बेहतर और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ही प्रीमियम इंटीरियर्स को दिया जा सकता है।

कितना ताकतवर होगा इंजन

रिपोर्ट्स के मुताबिक जीप की नई एसयूवी में सिट्रॉएन का ही 1.2 लीटर इंजन दिया जा सकता है। इसे टर्बो के साथ लाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें कंपनी 1.5 लीटर का इंजन भी दे सकती है। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से एसयूवी को 109 बीएचपी के साथ 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। जिसके साथ छह स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिल सकता है।

कितनी होगी कीमत

कंपनी की ओर से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपनी नई एसयूवी को 20 लाख रुपये से कम कीमत पर भारतीय बाजार में पेश कर सकती है। फिलहाल कंपनी की ओर से सबसे सस्ती एसयूवी के तौर पर कंपास को ऑफर किया जाता है, जिसकी कीमत 20.69 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू हो जाती है।

इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! नया वाहन लेने पर मिलेगी 10 हजार की छूट; जानें डिटेल

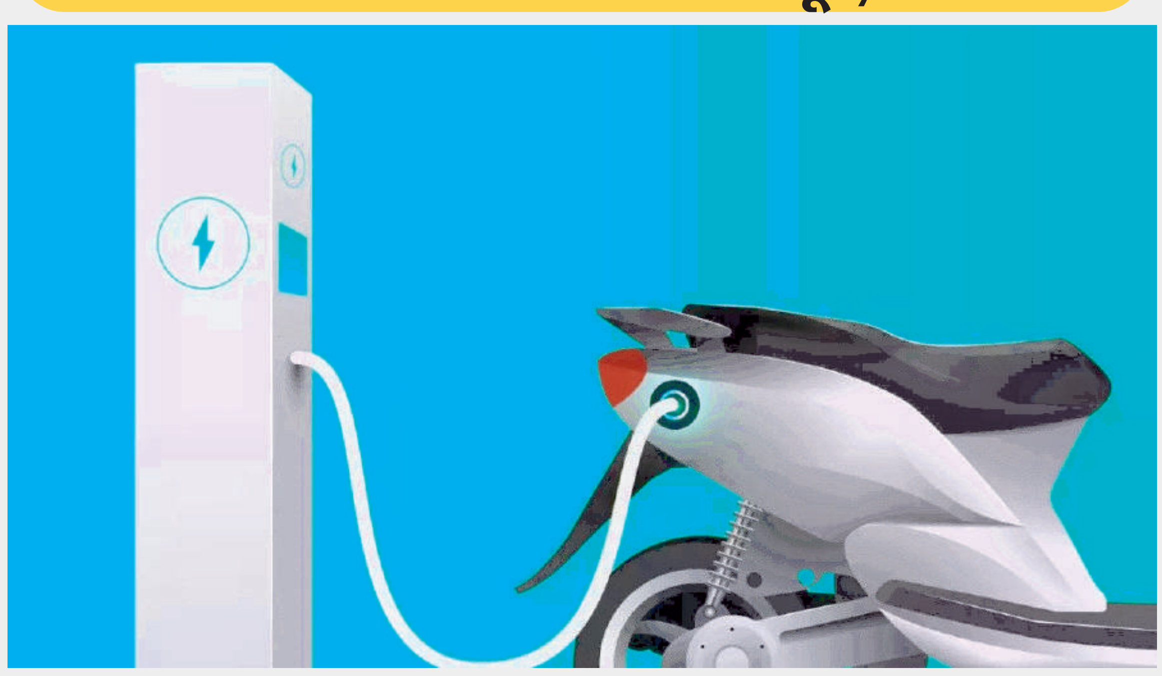

देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये के आउटले वाली एक नई योजना का एलान किया है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि योजना के तहत प्रति दोपहिया वाहन के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सहायता प्रदान करना है।

नई दिल्ली। देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये के आउटले वाली एक नई योजना का एलान किया है। ये योजना अप्रैल से जुलाई यानी चार महीने तक चलेगी और इसका लाभ दोपहिया और तिपहिया वाहनों को मिलेगा।

दोपहिया वाहनों को मिलेगी इतनी मदद

फेम-2 योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था, उसका दूसरा चरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहा है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि योजना के तहत प्रति दोपहिया वाहन के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सहायता प्रदान करना है।

ई-रिक्शा और ई-कार्ट को भी मिलेगी सब्सिडी

छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद के लिए 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ऐसे 31,000 से अधिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बड़े तिपहिया वाहन की खरीद पर वित्तीय सहायता 50,000 रुपये होगी। फेम योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों को मिलेगी।

क्या आप CAA के विरोधी हैं? यदि हाँ, तो....

नीरज कुमार दुबे

जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं उनसे हमारे कुछ सवाल हैं। क्या वह एक बार भी उन बस्तियों में गये हैं जहां पड़ोसी देशों से आये शरणार्थी रह रहे हैं? भारत में रह रहे शरणार्थियों को अपने मूल देश में धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ भ्रम फैलाने का खेल शुरू हो चुका है। कुछ लोग इस कानून पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं तो कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कुछ विपक्षी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस कानून को हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे जबकि वह जानते हैं कि केंद्रीय कानून में हस्तक्षेप करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मगर वोटों की राजनीति के लिए वह कुछ भी बोल रहे हैं। इस क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री तो सबसे आगे निकल गये और सीएए का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अमर्यादित शब्द का उपयोग करते हुए कह दिया है कि ये क्या बदतमीजी है।

जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं उनसे हमारे कुछ सवाल हैं। क्या वह एक बार भी उन बस्तियों में गये हैं जहां पड़ोसी देशों से आये शरणार्थी रह रहे हैं? भारत में रह रहे शरणार्थियों को अपने मूल देश में धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उनके सामने विकल्प थे या तो धर्मांतरण कर लो या मर जाओ या देश छोड़ दो। उन्होंने देश छोड़ कर भारत में शरण ली लेकिन यहां की नागरिकता नहीं होने के चलते उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। यही नहीं कोई उन्हें काम पर भी नहीं रखता क्योंकि वह अपनी पहचान साबित नहीं कर सकते। ऐसे में कम पैसों में ज्यादा मजदूरी करके वह किसी तरह अपना पेट पालते हैं, उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं होता और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भी इलाज में परेशानी होती है क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं है।

जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं क्या उनमें से एक ने भी इस कानून के नियमों को पूरी तरह से पढ़ा है? जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं क्या उनमें जरा भी मानवता नहीं है? जो लोग कह रहे हैं कि इसमें पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया क्या वह इस बात को नहीं जानते कि मुस्लिमों को इस्लामिक देश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता? अगर वह वहां किसी तरह परेशान भी हैं तो दुनिया में कई इस्लामिक देश हैं जहां वह बस सकते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए हिंदू बहुलता वाला एक ही देश भारत है जहां वह आ सकते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि सीएए में मुस्लिमों को शामिल नहीं कर भारत के संविधान का उल्लंघन किया गया है, उन्होंने शायद गृह मंत्रालय का बयान नहीं पढ़ा है। इसके अलावा, भारत कैसे सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है और कैसे अपने अल्पसंख्यकों का खास ख्याल रखता है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग से मंत्रालय है। यही नहीं, भारत में वक्फ एक्ट के तहत मुस्लिमों के लिए अलग से भूमि अधिकार कानून है। साथ ही भारत में आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष धार्मिक शिक्षा अधिकार कानून है। यही नहीं भारत में एचआरसीई एक्ट के तहत मंदिरों की संपत्ति और प्रबंधन से जुड़े तमाम अधिकार राज्य सरकारों के हाथ में हैं मगर किसी अन्य धर्म से जुड़े स्थलों पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।

लेकिन हल्ला मचाने वालों का एक ही लक्ष्य है कि झूठ इतनी बार बोलो और इतना तेज बोलो कि सच दब कर रह जाये। मगर सच दब नहीं सकता। जिसके मन में सीएए को लेकर जरा भी शक है उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान को पढ़ना चाहिए जिसमें कहा गया है कि नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं। मंत्रालय ने सीएए के संबंध में मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका को दूर करने की कोशिश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि ''इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।'' गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। बयान में कहा गया है कि नागरिकता कानून का वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है, जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं।

हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि उन तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह खराब हुई है। हालांकि, इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते, कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया कि यह कानून अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है। कानून की आवश्यकता बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ प्रवासियों को इन देशों में वापस भेजने के लिए कोई समझौता नहीं है। बयान में कहा गया है कि यह नागरिकता कानून अवैध प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है। इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता अनुचित है कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6, जो प्राकृतिक आधार पर नागरिकता से संबंधित है, के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है।

बयान में कहा गया कि अन्य धर्मों वाले भारतीय नागरिकों की तरह भारतीय मुस्लिमों के लिए आजादी के बाद से उनके अधिकारों की स्वतंत्रता और अवसर को कम किए बिना, सीएए ने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आने वाले लोगों के उत्पीड़न की पीड़ा को कम करने तथा उनके प्रति उदार व्यवहार दिखाने के उद्देश्य से नागरिकता के लिए आवेदन की योग्यता अवधि को 11 से कम कर पांच साल कर दिया है। सीएए लाने के औचित्य पर जोर देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि उन तीन देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए यह कानून, भारत की उदार संस्कृति के अनुसार उनके सुखी और समृद्ध भविष्य के लिए उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर देता है। बयान में कहा गया है कि नागरिकता प्रणाली में जरूरत के अनुसार बदलाव लाने और अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए इस कानून की आवश्यकता थी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है, जिसे इस्लाम के अपने तौर-तरीकों का पालन करने के लिए उन तीन इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

बहरहाल, सीएए के क्रियान्वयन के खिलाफ असम सहित देश के कुछ हिस्सों में भले विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है लेकिन सीएए लागू किये जाने पर हिंदू-सिख शरणार्थियों में खुशी का माहौल है। पहचान मिलने की उम्मीद की खुशी में शरणार्थियों का कहना है कि यह उनके लिए पुनर्जन्म की तरह है। कई कई दशकों से भारत में रह रहे शरणार्थियों को अब उम्मीद है कि सबसे बुनियादी चीज 'पहचान' उन्हें मिलने के बाद उनके और उनके बच्चों के लिए आगे का जीवन आसान हो जायेगा। देखा जाये तो सीएए का विरोध करने की बजाय इस कानून के जरिये इतने लोगों के जीवन में खुशी लाने के लिए भारतीय संसद का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए।

संपादक की कलम से

2024 का 'नागरिक शास्त्र'

नागरिकता संशोधन बिल को 2016 में संसद में पेश किया गया। दिसंबर, 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया। जाहिर है कि कानून बनाने की पटकथा को अंतिम रूप दे दिया गया, लेकिन 4 साल 3 माह की लंबी अवधि के बाद कानून की अधिसूचना तब जारी की गई, जब आम चुनाव की घोषणा कुछ दिन बाद होने ही वाली थी। इस संदर्भ में अधिसूचना के समय पर कठोर सवाल किए जाने स्वाभाविक हैं। अधिनियम के नियम, उसकी पात्रता और शर्तें आदि तय करने में इतना लंबा वक्त गुजार दिया गया, यह वाकई आश्चर्यजनक स्थिति है। अब एक तरफ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की अधिसूचना जारी की गई है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से इंकार कर दिया है। उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी यह बयान दिया है कि पहले सभी संशयों और असमंजस को दूर कर लेना चाहिए था। वैसे किसी भी मुख्यमंत्री को यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि संसद द्वारा पारित और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी कानून को लागू करने से स्पष्ट इंकार कर सके। यह परोक्ष रूप से संघीय टकराव की स्थिति है, जिस पर सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ को फैसला देना पड़ सकता है। सीएए को ध्रुवीकरण अथवा मुस्लिम-विरोध का नागरिक शास्त्र कहा जा सकता है, जो एक निश्चित हद तक 2024 के आम चुनाव को प्रभावित करेगा। वैसे इसमें भी अद्र्धसत्य ही है।

बेशक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के पीड़ित, अत्याचारों को झेलते उन देशों के घोर अल्पसंख्यकों-हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी-को ही भारत की नागरिकता मुहैया कराने की व्यवस्था सीएए में की गई है, लिहाजा भाजपा अपने जनाधार में ध्रुवीकरण करा चुनावी फायदा उठा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा इसका सफल प्रयोग बंगाल में कर चुकी है। विरोधियों की आशंका, उनके असमंजस और डर बयां किए जा रहे हैं कि सीएए का लिंक एनआरसी से है। सीएए के जरिए मुसलमानों के एक तबके की नागरिकता छीनी जा सकती है। ऐसी दलीलें महज अफवाहें हैं और देश में विभाजनकारी हालात पैदा करने को विरोध किया जा रहा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा में कुछ संगठन आंदोलित हो चुके हैं। याद रहे कि राजधानी दिल्ली के 'शाहीन बाग' इलाके में इसी मुद्दे पर मुसलमानों ने 100 दिन का आंदोलन चलाया था और बाद में पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भी भडक़े थे, लिहाजा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 'फ्लैग मार्च' तक निकाला है। फिलहाल करीब 18 लाख 74000 आवेदन इन तीनों पड़ोसी देशों से आ चुके हैं। सबसे ज्यादा शरणार्थी 16.39 लाख पाकिस्तान से आए हैं या आना चाहते हैं। पाकिस्तान में हिंदू आदि अल्पसंख्यक 1.18 फीसदी, बांग्लादेश में 8.5 फीसदी और अफगानिस्तान में मात्र 0.04 फीसदी हैं। उनके लिए भारत 'मानवतावादी धार्मिक संरक्षक देश' है। ये तीनों इस्लामी देश हैं, लिहाजा कानून में मुसलमानों की नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं है। गौरतलब यह भी है कि नागरिकता का ऐसा कानून 1955 से हमारे देश में लागू है, जब जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे।

उसमें 6 संशोधन भी किए जा चुके हैं। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 बना कर इसे व्यापकता दी है। पात्र शरणार्थी एक निश्चित वेबपोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकार प्राप्त समिति इस पर अंतिम फैसला लेगी। इसके प्रमुख निदेशक (जनगणना) होंगे और 7 अन्य सदस्य भी समिति में होंगे। कानून के नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि सीएए में नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। वैसे भी संविधान में उल्लेख है कि भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। आज जो सीएए विरोधी राजनीतिक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वे हिंदू-मुसलमान की सियासत ही है, ताकि इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट बटोरे जा सकें। हिंदू आदि का अधिकतम धुरवीकरण भाजपा के पक्ष में होना चाहिए। इस कानून का विरोध जायज नहीं लगता।

राय

पिंजरे में दावत

सियासत यूं तो महत्त्वाकांक्षा का दाना है, लेकिन चुगने वालों की दावत कई बार पिंजरों में फंसा देती है। अपने-अपने मुकाम के संघर्ष में हिमाचल कांग्रेस के छह विधायक यूं तो एक प्रभावशाली धड़ा है, लेकिन सत्ता के संकट में उनके पक्ष में अनिश्चितता है। राज्यसभा सीट गंवा बैठी कांग्रेस भी फिलहाल दूध से धुली नxर नहीं आ रही, लेकिन अदालत की पहली दरख्वास्त पर बागी विधायकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रास्ता आसान नहीं किया। माननीय अदालत ने बागी विधायकों की फरियाद पर चंद टिप्पणियां तो कीं, लेकिन किसी फैसले की शरण उन्हें नहीं दी। जिरह से जुबां तक और जुबां से मुकाम तक, हिमाचल में सरकार बनाम बागी विधायकों के बीच सियासी समीकरण रेंग रहे हैं, तो भाजपा के साथ भी सुर जोडऩे की कलह विद्यमान है। यानी यह मुद्दा घिसट कर पेचीदा और लोकसभा चुनाव का पसंदीदा शायर बन गया है। इसी संदर्भ में अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि बागी अपनी कानूनी लड़ाई के लिए पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, तो बताने के मार्ग पर मील पत्थर लगाने पड़ेंगे। अपने निर्णय की धाक पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जिस शिद्दत से व्हिप की सूली पर बागियों की सदस्यता छीनी है, उससे राजनीति बेरहम हुई या सत्ता ने खुद को सलामत कर लिया। सत्य के दरवाजे पर पहुंचा मुद्दा भले ही बागियों की मुखबिरी कर रहा है, लेकिन हिमाचल के लिए यह घटनाक्रम अपमान की श्रेणी में आकर पढ़े-लिखे लोगों के राज्य पर प्रश्न खड़े कर रहा है। सवाल बागियों पर हैं, तो सरकार पर भी उठे हैं और सामने बर्जिश कर रही भाजपा की मांसपेशियों पर भी हैं। बेशक हिमाचल अब मध्यप्रदेश या महाराष्ट्र नहीं बन सका, लेकिन कुल नौ विधायकों के लिए की गई किलेबंदी का गणित इतना भी सरल नहीं कि माथापच्ची न की जाए। भाजपा की सफलता का चक्र कांग्रेस से कहीं व्यापक, तीव्र व सुदृढ़ है, लेकिन हिमाचल के प्रकरण में कांग्रेस अभी तक विफल नहीं हुई है। भले ही पार्टी से राज्यसभा की एक सीट छीन ली गई या नौ विधायकों की पेशबंदी में कांग्रेस के पांव फंसे हैं, लेकिन भाजपा के लिए इस सीरियल की कहानी टेढ़ी हो चुकी है। मामला अदालत की सर्वोच्चता में किस करवट बैठता है, इसे लेकर राजनीतिक चुंबक भी परेशान हैं। बागी विधायकों पर आया विधानसभा अध्यक्ष का फैसला प्रतिकूल बना रहेगा या सुप्रीम कोर्ट से राहत के इतंजार में आगामी सदियां गुजर जाएंगी। जो भी हो, आगामी सोमवार तक सरकार के पास अपना सिक्का जमाने का एक और अवसर तो है ही और इसी के परिप्रेक्ष्य में एक बागी निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और दूसरे कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के पिता एवं पूर्व नौकरशाह राकेश शर्मा के खिलाफ हुई एफआईआर की जद में आई जमीन खिसक रही है या ऐसे ताबड़तोड़ हमलों की बिसात पर सियासी कत्ल होते रहेंगे। कहना न होगा कि बागी विधायकों की रियासत को बागी होने से बचाने के लिए एक नई या पीछे रह गई कांग्रेस को इंचार्ज बनाया जा रहा है। अब संगठन व सत्ता का एक साम्राज्य है और जिसे मुख्यमंत्री चला रहे हैं। बेशक कांग्रेस आलाकमान ने समन्वय समिति के गठन में सत्ता को संगठन और संगठन को सत्ता के करीब दिखाने का प्रयत्न किया है, लेकिन सारे घटनाक्रम का जादू अनेक मुट्ठियों में बंद है। और तो और, अदालत ने भी कानून की मुट्ठियों में किसी फैसले की तहरीर को छुपा रखा है। समन्वय समिति की खोज में कौल सिंह ठाकुर व रामलाल ठाकुर का आगमन आशा जगाता है। कांग्रेस के सन्नाटों में खो रहे ऐसे चेहरों के आगमन से सत्ता का अनुभव पुख्ता हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस के रक्षा कवच मुखातिब हैं और सरकार के करतब भी चमक पैदा कर रहे हैं। सारी अशांति के ऊपर फैलाई गई चादर कितना असर रखती है, इसका अंदाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा चुनाव तक बहुत कुछ प्रमाणित करेगा।

उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सचेत होने की जरूरत

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अन्य कानूनों की अपेक्षा उपभोक्ताओं को अधिक संरक्षण प्रदान करता है। उपभोक्ताओं के विवादों का शीघ्र और उचित निपटारा करने के लिए अर्ध-न्यायिक पद्धति को बनाया गया है। इसमें जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है'

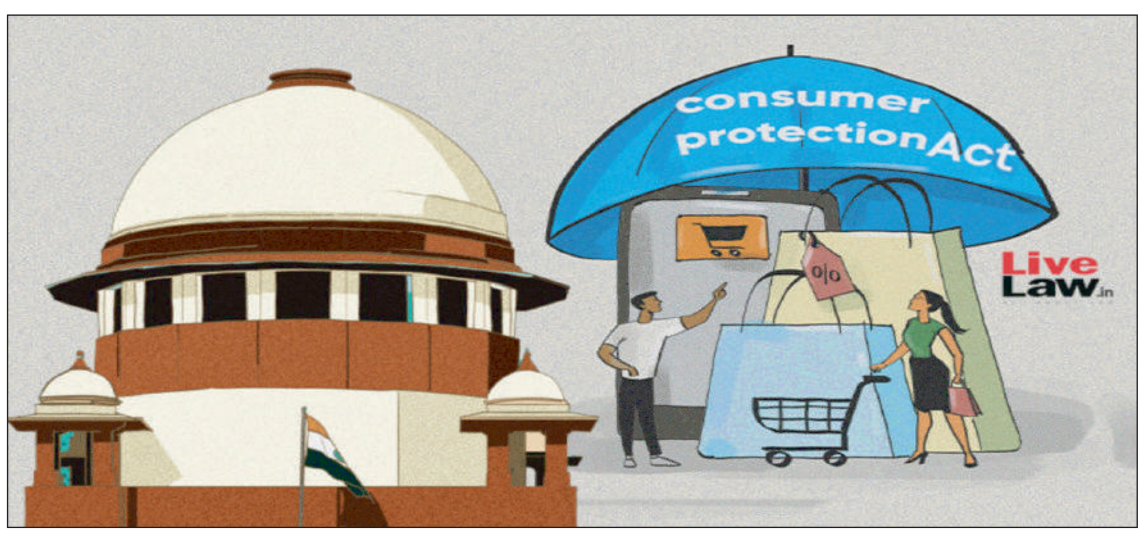

खाद्य पदार्थों में मिलावट आज विश्वव्यापी समस्या है। बहुत से देशों में इसने भयावह रूप धारण कर लिया है। अधिकांश लोग यह जाने बिना कि उसमें मिलावट है, खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जिससे उपभोक्ता विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, भोजन की कमी और अनुचित लाभ की लालसा के कारण मिलावट ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। इस तरह के कदाचार का अंतिम लक्ष्य ज्यादातर उपभोक्ता होते हैं जो अनजाने में इन खाद्य पदार्थों को खरीदते और खाते हैं तथा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं। मिलावटी भोजन से उपजी बीमारियों के उपचार के लिए बाजार में दूषित दवाओं से या तो मौत हो जाती है या उपचार ताउम्र ही चलता रहता है जिससे उस परिवार की माली हालत खराब हो जाती है। दूषित दवाइयों से सारी दुनिया ही ग्रसित है और ये मौत का कारण भी हैं। 2006 में पनामा में कम से कम 366 लोगों की मौत का कारण बना दूषित कफ सिरप। भारत में बने कफ सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौतें, जम्मू-कश्मीर में खांसी/जुकाम की दवा से 10 बच्चों की मौतें, उज्बेकिस्तान में इंडियन कफ सिरप से 18 बच्चों की मौतें भी उल्लेखनीय हैं। इसी तरह 1998 में दिल्ली में 33 मौतें, 1986 में मुंबई में 14 मौतें और 1973 में चेन्नई में 14 मौतें हुई थी। दूषित दवाओं से ऐसी और बहुत सी मौतें हुई हैं और हो रही हैं। ये सब दवाइयों में गुणवत्ता की उपेक्षा के कारण हैं। पूरे विश्व में दूषित दवाओं की पूर्ति के लिए चीन और भारत की छवि खराब है।

दूषित दवाओं को बनाने में हिमाचल प्रदेश भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हिमाचल में बीबीएन एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब माना जाता है। यहां 380 से ज्यादा फार्मा उद्योग हैं। प्रदेश में 675 फार्मा उद्योग कार्यरत हैं। देश में दवाइयों की खपत के बाद करीब 183 अन्य देशों में दवाइयां निर्यात की जाती हैं। 25-30 हजार करोड़ रुपए का सालाना व्यवसाय यहां होता है। प्रदेश के फार्मा उद्योग में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। पिछले 5 सालों में दवाइयों के 8000 सैंपल फेल हुए। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए उनमें शुगर, संक्रमण, एंटीबायोटिक, एलर्जी, ब्लड क्लोट व दर्द निवारक दवाइयां शामिल हैं। विश्व भर में हिमाचल की छवि को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल को इस संदर्भ में नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता की टेस्टिंग लैब बने और दवाओं की गुणवत्ता चैक होने के बाद ही बाजार में भेजें। प्रमुख खाद्य पदार्थों में भी मिलावट होती है। इनमें गेहूं-चावल में कंकड़/मिट्टी, सरसों तेल में सस्ता पाम आयल, हल्दी में लैड क्रोमेट और पीली मिट्टी, दूध में यूरिया व डिटर्जेंट, मिर्च में लाल ईंट पत्थर पाउडर, फल-सब्जी में कृत्रिम रंग, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर मिलावटी दूध की चाय आदि शामिल हैं जिनसे विभिन्न बीमारियां होती हैं, जैसे हृदय रोग, गुर्दों पर दुष्प्रभाव, लीवर-मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव, पेट रोग आदि। बहुत से लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं। खाद्य सुरक्षा कानूनों के ढीले कार्यान्वयन और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता की कमी के कारण ही खाद्य पदार्थों में मिलावट बड़े पैमाने पर हो रही है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने, बाजार में होने वाली ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी चीजों का वितरण, तय मूल्य से ज्यादा दाम वसूलना, बिना मानक चीजों की बिक्री, ठगी, नापतोल में अनियमितताएं, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देने के अलावा उपभोक्ताओं के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए हर साल 15 मार्च को नए थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।

उपभोक्ता आंदोलन के जनक अमरीकी राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक राल्फ नादर थे। उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने के लिए 1962 में अमरीकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी द्वारा अमरीकी कांग्रेस में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की याद में 15 मार्च को चुना गया था। 15 मार्च 1983 को उपभोक्ता समूहों के लिए एक संघ 'कंज्यूमर्स इंटरनेशनल' द्वारा मनाया गया था। कंज्यूमर इंटरनेशनल दुनिया भर के उपभोक्ता समूहों के लिए सदस्यता संगठन है। 1 अप्रैल 1960 को स्थापित, इसके 120 देशों में 250 से अधिक सदस्य संगठन हैं। इसका मुख्य कार्यालय लंदन में है। भारत में पहला राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 1986 को मनाया गया था। उपभोक्ता के छह अधिकार हैं: सुरक्षा, सूचना, चुनने, सुने जाने, निवारण और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन अधिकारों के अलावा शोषण से बचने के लिए हमारे कुछ कत्र्तव्य हैं। वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता कुछ मानकों द्वारा तय की जाती है। इसमें कोई भी सामान खरीदने से पहले उन मानकों को देख-समझ कर ही वस्तु क्रय करनी चाहिए।

भारत में स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे राष्ट्रीय संविधान और वैधानिक कानूनों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कानूनों में भी वैधता दी गई है। इसी के दृष्टिगत भारत सरकार और राज्य सरकारों ने बहुत से कानूनों और अधिनियमों को पारित कर दूषित दवाओं और खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के कदम उठाए हैं, जैसे सुरक्षित भोजन के संबंध में मुख्य कानून है 1954 का खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम। यह कानून 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अन्य कानूनों की अपेक्षा उपभोक्ताओं को अधिक संरक्षण प्रदान करता है। उपभोक्ताओं के विवादों का शीघ्र और उचित निपटारा करने के लिए अर्ध-न्यायिक पद्धति को बनाया गया है। इसमें जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। कुल मिलाकर देखें तो कई कानून होने के बावजूद भारत में उपभोक्ता अभी जागरूक नहीं हैं। उन्हें इस संबंध में जागरूक करने की जरूरत है।

सत्यपाल वशिष्ठ

अली बाबा और पचास मोर

मैं उनके काव्य संग्रहों के चौके छक्कों का घायल हूं। दो साल पहले वे पता नहीं कविता के आसमान में कहां से पुच्छल तारे की तरह अवतरित हुए औ फिर देखते ही देखते कविता के जगत में उन्होंने वह कहर बरपाया कि 'वह कहर बरपाया कि 'अब तो उनके काव्य संग्रह सौष्ठव को देख कबीर-तुलसी भी दांतों तले अंगूठा दबाने को विवश हैं। आह! हिंदी जगत में ऐसा कवि सदियों के बाद पैदा होता है जिसके नख शिख से कुछ झरता है तो बस काव्य संग्रह। मैं बापुरो! इधर एक कविता लिखने को भी महीनों लगा देता हूं। कविता होती है कि लाख जोर मारने के बाद भी पेट से बाहर आने से साफ मना कर देती है। कई बार तो वे मेरी कविता की पहली लाइन फाइनल होने से पहले ही पाठकों के मुंह पर ठा से काव्य संग्रह दे मारते हैं। तब मुझे लगता है कि उनकी कलम से कविताएं नहीं, संग्रह बरसते हों सचिन तेदुंलकर के बल्ले की तरह। दूसरे शब्दों में उन्हें आप कविता का सचिन भी कह सकते हैं। अबके ज्यों ही अपनी फेसबुक वाल पर उन्होंने एक बार फिर चकित कर देने वाली पोस्ट डाली कि इसी हफ्ते उनके एक साथ छह काव्य संग्रह एक साथ पाठकों से अधिक उनके समकालीन लेखकों के बीच तहलका मचाने आ रहे हैं तो मेरा कलेजा मेरे मुंह के बदले कहीं और को हो लिया। तब मैंने अपने कलेजे को समझाते कहा, 'पगले! मुहावरे में कलेजा मुंह को आता है और एक तू है कि''। पर तब मुझे लगा ज्यों उस वक्त मुहावरे को बदलने के मूड में हो वह जैसे। मेरा ही क्या! मेरे जैसे पता नहीं कितने लेखकों के साथ उनकी फेसबुक वाल पर मेरा जैसा पढ़ कर हुआ होगा! तब मैंने अपने आपको जी भर कोसा! क्या खाक लेखन करता है तू! अपने को बड़ा वरिष्ठ कवि अपने आप ही कहता फिरता है। इसे लेखन कहता है तू! उन्हें देख! इसे कहते हैं लेखन!

उनकी कलम जब चलती है कविता नहीं लिखती। कविता संग्रह लिखती है। बच्चे! तू तो एक साथ पांच कविताएं हिंदी साहित्य को नहीं दे पाया और उधर अपने अलीबाबा हैं कि एक साथ छह छह कविता संग्रह हिंदी साहित्य को सौंप हिंदी साहित्य को समृद्ध किए जा रहे हैं। एक दो कविता संग्रह हिंदी साहित्य को देना वे उसी तरह अपना अपमान समझते हैं जैसे धांसू बल्लेबाज दौड़ कर एक दो रन बनाना अपना अपमान समझता है। अपने आप बंदा जो हो, सो हो, पर जो धड़ाधड़ अपने कविता संग्रहों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहा हो, उस पर हिंदी साहित्य की सभी विधाओं का गर्व होना चाहिए। कल पता नहीं क्यों अपनी साहित्यिक शर्म को छिपाता मैं उनसे मिलने उनकी साहित्यिक फैक्टरी में जा पहुंचा। उस वक्त वे अपने अगले काव्य संग्रह की भूमिका घिस पिट रहे थे। जाते ही मैंने उनके साहित्यिक पांव पकड़े, 'हे साहित्य केसरी! तुम धन्य हो। अनुज तुम्हारा चेला होना चाहता है।' तब वे मुझसे अपने साहित्यिक पांव और भी जोर से पकड़ाते उन्हें छुड़वाने का नाटक करते बोले, 'उठो वत्स! लिखने वाला मैं कौन होता हूं? सब मां सरस्वती की कृपा है। साहित्य में उनकी कृपा के बिना चुटकुला भी नहीं लिखा जा सकता।' 'हे साहित्य के देदीप्यमान धमकेतू! आखिर आप इतने कविता संग्रह एक साथ कैसे निकाल लेते हो? हो सके तो अर्जुन की जिज्ञासा शांत करो'।

मेरे प्रश्न को सुन वे मुझे घूरे! फिर इधर उधर देखने के बाद सहज हो बोले, 'किसी को कुछ बताओगे तो नहीं?' 'नहीं!' मैंने मुर्गा बन उनके दोनों कान पकड़ते कहा। 'तो सुनो वत्स! बहुत आसान है। अगले हफ्ते चार और कविता संग्रह पाठकों को दे रहा हूं'। सुनते ही मेरा दिमाग चक्कराने लगा और दिल की धडक़न कम होने लगी तो उन्होंने मुझे जीवनदान देते अपने मुंह से मेरे मुंह में अपनी हवा डालते मेरे पाइरेटिड फेफड़ों में साहित्यिक हवा भरते कहा, 'मेरे पास सौ कविताएं हैं।' 'पर मेरे पास तो सवा सौ हैं गुरुदेव! फिर भी प्रकाशक कहता है बीस और लिखो तो काव्य संग्रह दिखने लायक लगे।' 'बस, दिल पर हाथ रख हर बार अगली कविता के शीर्षक से नया काव्य संग्रह निकाल देता हूं।' 'मतलब?' 'मतलब ये कि अभी मेरे पास पचास और कविता संग्रहों के शीर्षक हैं। पांच सात इस बीच और काट पीट ही लूंगा। तो कुल मिलाकर 'मैं चाहूं तो अभी मैं पचास पचपन कविता संग्रह और निकालने का हकदार हूं।' 'तो अब तक आपके कितने कविता संग्रह निकल चुके हैं?' 'पचास! और पचास कविता संग्रहों के शीर्षक अभी मेरी जेब में हैं।' उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप मेरे सिर पर अपने चमत्कारी साहित्यिक पेन से कुछ लिखा और फिर मुस्कुराते हुए साहित्यिक कुकर्म में लीन हो गए।

अशोक गौतम

वनस्पति तेल आयात में आई 13 प्रतिशत की कमी, फरवरी में 9.75 लाख टन पहुंचा

वनस्पति तेल आयात फरवरी में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत घटकर लगभग 9.75 लाख टन रह गया है। जबकि 2023 में समान अवधि में यह 1114481 टन था। वहीं कुल आयात में खाद्य तेल का हिस्सा घटकर 967852 टन रह गया। फरवरी 2023 में यह 1098475 टन था। भारत खाद्य तेलों की अपनी 50 प्रतिशत से अधिक घरेलू जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है।

नई दिल्ली। भारत का वनस्पति तेल आयात फरवरी में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत घटकर लगभग 9.75 लाख टन रह गया है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 11,14,481 टन था। उद्योग संगठन साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एसईए) ने बुधवार को कहा कि कुल आयात में खाद्य तेल का हिस्सा घटकर 9,67,852 टन रह गया। फरवरी, 2023 में यह 10,98,475 टन था। गैर खाद्य तेलों का आयात भी एक साल पहले की समान अवधि के 16,006 टन से घटकर 7,000 टन रह गया। नवंबर, 2023 से फरवरी, 2024 के दौरान, वनस्पति तेलों का कुल आयात 21 प्रतिशत घटकर 46,47,963 टन रह गया, जो पिछले तेल वर्ष की इसी अवधि में 58,87,900 टन था।

खाद्य तेलों का आयात में कमी

तेल वर्ष 2023-24 के पहले चार माह के दौरान खाद्य तेलों का आयात घटकर 46,15,551 टन रह गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 58,44,765 टन था। इंडोनेशिया और मलेशिया से भारत पाम तेल का आयात करता है। वह अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन तेल का आयात करता है। खाद्य तेल आवश्यकताओं के लिए पाम तेल की उपलब्धता में कमी आई है क्योंकि मुख्य दो उत्पादक देश मलेशिया और इंडोनेशिया इसे बायोडीजल के उत्पादन के लिए लगा रहे हैं। तेल वर्ष 2023-24 की नवंबर-फरवरी अवधि के दौरान अखाद्य तेलों का आयात घटकर 32,412 टन रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 43,135 टन था।

इस साल हो सकती है कीमतों में बढ़ोतरी

भारत खाद्य तेलों की अपनी 50 प्रतिशत से अधिक घरेलू जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है। देश इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का आयात करता है। यह अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन तेल का आयात करता है।

एसईए ने कहा कि फरवरी 2024 में वनस्पति तेल के आयात में गिरावट जारी रही। खाद्य तेल जरूरतों के लिए पाम तेल की उपलब्धता में कमी आई है क्योंकि मुख्य दो उत्पादक मलेशिया और इंडोनेशिया इसे बायोडीजल के उत्पादन के लिए लगा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इस साल कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। एसईए ने कहा कि इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन, जो वैश्विक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, 2024 में या तो मामूली रूप से बढ़ने की संभावना है या पिछले साल के स्तर से घटने की संभावना है, क्योंकि वृक्षारोपण की उम्र बढ़ने और विस्तार कैप आउटपुट की कमी है।

गोल्ड लोन फ्रॉड पर वित्त मंत्रालय सतर्क, सरकारी बैंकों को गोल्ड लोन बुक्स की समीक्षा करने के दिए निर्देश

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। इस पत्र में विभाग ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वह गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। दरअसल विभाग को नियामक मानदंडों का अनुपालन के मामले देखने को मिला है। इन मामलों को देखने के बाद विभाग ने सभी पीएसयू बैंक को यह निर्देश दिया।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वह गोल्ड लोन पोर्टफोलियो (Gold Loan Portfolio) की समीक्षा करें। दरअसल, मंत्रायल ने नियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के मामले देखें हैं। इसके बाद वित्त मंत्रायल ने सभी पीएसयू बैंक को यह निर्देश दिया।

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के प्रमुखों को एक संबोधित पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने गोल्ड लोन (Gold Loan) से संबंधित अपनी सिस्टम और प्रोसेस पर गौर करने को कहा है।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने पीटीआई एजेंसी को बताया कि हमने बैंकों से गोल्ड लोन कारोबार की व्यापक समीक्षा करने को कहा है।

पिछले महीने भी इस संबंध में एक निर्देश जारी हुआ था। इसमें बैंक को शुल्क और ब्याज के कलेक्शन और गोल्ड लोन अकाउंट को बंद करने से संबंधित विसंगतियों को ठीक करने की सलाह दी गई थी।

वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गए पत्र में विभिन्न चिंताओं को उजागर किया गया है। इसमें अपेक्षित स्वर्ण संपार्श्विक (Requisite Gold Collateral) के बिना गोल्ड लोना का वितरण, चार्ज का कलेक्शन और कैश में रिपेमेंट के संबंध में विसंगतियां शामिल हैं।

डीएफएस ने बैंकों से 1 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2024 तक पिछले दो साल की अवधि की गहन समीक्षा करने का आग्रह किया। इस समीक्षा से यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी गोल्ड लोन बैंकों की नियामक आवश्यकताओं और आंतरिक नीतियों के पालन के तहत ही दिया गया है।

गोल्ड हुआ महंगा

बीते कुछ दिनों से गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। गोल्ड की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले एक महीने में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,365 रुपये से बढ़कर 67,605 रुपये हो गई है।

ऐसे में बैंक प्रमुख को मिले पत्र के अनुसार विभाग को गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के संबंध में गैर-अनुपालन के मामले सामने आए हैं और इसलिए विभाग ने यह सलाह जारी की है।

देश के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पास अकेले दिसंबर 2023 तक 30,881 करोड़ रुपये का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है।

तीसरी तिमाही के अंत में पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) का गोल्ड लोन एक्सपोजर 5,315 करोड़ रुपये था जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) का गोल्ड लोन 3,682 करोड़ रुपये था।

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बैंक या गोल्ड लोन फाइनेंस फर्म ज्वेलरी के मूल्य का केवल 75 प्रतिशत ही दे सकते हैं। हालाँकि, ग्राहक की कठिनाई को कम करने के लिए COVID-19 अवधि के दौरान छूट प्रदान की गई थी।

आरबीआई ने गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सोने के आभूषणों और आभूषणों को गिरवी रखकर बैंकों द्वारा स्वीकृत लोन के लिए मूल्य पर लोन (एलटीवी) को अगस्त 2020 में 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया था।

400 रुपये सस्ता हुआ सोना, चेक करें आपके शहर में कितनी है गोल्ड प्राइस

बुधवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के नए दाम जारी हो गए हैं। आज वायदा कारोबार में सोना और चांदी महंगा हुआ है। इस हफ्ते सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आज राजधानी दिल्ली में चलिए जानते हैं कि आपके शहर में 24 कैरेट का 10 ग्राम गोल्ड कितने रुपये में मिल रहा है।

नई दिल्ली। 13 मार्च 2024 को सोना-चांदी के नए दाम जारी हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमतें 400 रुपये गिरकर 65,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। मंगलवार को सोने की कीमत 66,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार, विदेशी बाजारों में कमजोर रुझानों के बीच यह गिरावट देखने को मिली है। वहीं, चांदी भी 600 रुपये टूटकर 75,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गयी है।

वायदा बाजार में रही तेजी: आज वायदा कारोबार में सोना-चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। गोल्ड रिकॉर्ड स्तर के पार पहुंच गया है। अगर आप सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। दरअसल, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की वजह से हर शहर में इनकी कीमत अलग होती है।

क्या है आज आपके शहर में गोल्ड की कीमत

गुड रिटर्न के मुताबिक, आपके शहर में सोना-चांदी के लेटेस्ट रेट्स-

दिल्ली में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 65,990 रुपये है।
मुंबई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 65,840 रुपये है।
कोलकाता में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 65,840 रुपये है।
चेन्नई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,650 रुपये है।
हैदराबाद में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 65,840 रुपये है।
चंडीगढ़ में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 65,990 रुपये है।
जयपुर में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 65,990 रुपये है।
पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 65,890 रुपये है।

क्या आपको भी मिला है आयकर विभाग से Tax मिसमैच का नोटिस? तो करें यह काम

परिवहन विशेष न्यूज

अगर टैक्सपेयर आईटीआर फाइलिंग में कोई गलती कर देता है या फिर कोई गलत जानकारी दे देता है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजा जाता है। आयकर विभाग द्वारा भेजे गए टैक्स नोटिस को देखकर कई लोग घबरा जाते हैं। अगर आपके पास भी नोटिस आया है तो इस आर्टिकल में जानते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए।

नई दिल्ली। Income Tax Notice For ITR Mismatch: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) में मिसमैच मिला है। थर्ड पार्टी द्वारा दी गई जानकारी और टैक्सपेयर्स द्वारा दी गई जानकारी अलग होने की वजह से करदाता को आयकर विभाग द्वारा नोटिस भी मिल सकता है।

कई यूजर के पास इसको लेकर एसएमएस भी आया है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा है कि ये सिर्फ जानकारी है। इसे आयकर विभाग का नोटिस ना समझे।

दरअसल, टैक्यपेयर्स रिटर्न फाइल करते समय अपने इनकम संबंधित जानकारी देता है। यह सभी जानकारी करदाता की कंपनी और बैंक द्वारा भी दिया जाता है। ऐसे में कई बार कंपनी और करदाता द्वारा दी गई जानकारी अलग हो जाती है। इसको लेकर विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है।

अगर करदाता मिसमैज डिटेल्स को समय से पहले सही नहीं करता है तो उनके पास विभाग का नोटिस आ सकता है। करदाता को मिसमैच ढूंढने में आसानी हो इसके लिए आयकर विभाग ने इनकम टैक्स पोर्टल पर 'कांप्लायंस पोर्टल' की सुविधा दी है।

अगर आपको भी लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें कोई जानकारी गलत या फिर थर्ड पार्टी से अलग है तो आप इसे समय से पहले ठीक कर सकते हैं।

कैसे ठीक करें मिसमैच जानकारी

आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in) पर जाना है।

इसके बाद आपको लॉग-इन करना है।

अब आपको ई-वेरिफिकेशन के टैब में जाना है।

जो लोग रजिस्टर नहीं है उन्हें पहले साइन अप करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग-इन करके कंप्लाइंस पोर्टल पर जाना होगा।

अब ऑन-स्क्रीन को सेलेक्ट करके आपको सभी मिसमैच जानकारी शो हो जाएगी।

इसके बाद जो जानकारी गलत है उन्हें सही करना होगा।

इनसाइड

इन मामले में चीन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है भारत, यहां जानें जरूरी डिटेल

भारत दो प्रमुख मापदंडों यानी जीडीपी के अनुपात में निर्यात और सेवा निर्यात पर चीन से आगे निकल गया है। न्यू डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट-2024 में कहा गया है कि 2021 के बाद से भारत का जीडीपी के अनुपात में निर्यात चीन से अधिक हो गया है। जबकि निर्यात और आयात दोनों के मामले में देश का सेवा व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है।

नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में एकीकरण के संबंध में भारत दो प्रमुख मापदंडों जीडीपी के अनुपात में निर्यात और सेवा निर्यात पर चीन से आगे निकल गया है। डीएचएल और न्यूयार्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल आफ बिजनेस की तरफ से यहां जारी 'न्यू डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट-2024' में कहा गया है कि 2021 के बाद से भारत का जीडीपी के अनुपात में निर्यात चीन से अधिक हो गया है। जबकि निर्यात और आयात दोनों के मामले में देश का सेवा व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 और 2022 में जीडीपी के हिस्से के रूप में भारत का निर्यात और आयात तेजी से बढ़ा। देश में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का 23 प्रतिशत (2020 में 19 प्रतिशत से अधिक) और वस्तुओं और सेवाओं के आयात का हिस्सा जीडीपी के 26 प्रतिशत (2020 में 19 प्रतिशत से भी अधिक) पर पहुंच गया है।

टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट से पैदा होंगी 72 हजार नई नौकरियां, एन चंद्रसेखरन बोले - 2026 में बना

परिवहन विशेष न्यूज

आज असम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata Electronics) की चिप असेंबली सर्विस का शिलान्यास समारोह हुआ। इस समारोह में टाटा संस (Tata Sons) के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) ने कहा कि सेमीकंडक्टर प्लांट सभी सेक्टर की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा और इस प्लांट से लगभग 72000 लोगों को नौकरियां मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर 2026 तक पहला सेमीकंडक्टर चिप का सेट का प्रोडक्शन हो सकता है।

नई दिल्ली। भारत अब खुद सेमीकंडक्टर बनाने की राह पर है। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2026 तक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata Electronics) अपना पहला सेमीकंडक्टर (Semiconductor) सेट बना देगा। आज सेमीकंडक्टर को लेकर टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपडेट दिया है।

टाटा संस (Tata Sons) के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) ने कहा कि

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट धीरे-धीरे सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति करेगा और वह चरणबद्ध तरीके से सभी सेक्टर को सेवाएं देंगा। सेमीकंडक्टर के निर्माण से भारत में रोजगार के अवसर पैदा हुए। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 72,000 लोगों को नौकरियां मिली है।

आज असम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के 91,000 करोड़ रुपये के चिप मेन्यूफेक्चरिंग प्लांट और 27,000 करोड़ रुपये की चिप असेंबली सर्विस का शिलान्यास समारोह हुआ। इस समारोह में चंद्रशेखरन ने कहा कि हम जिस दिन शुरुआती लक्ष्य को हासिल कर लेंगे उसके बाद हम सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का विस्तार करेंगे।

इन सेक्टर की आवश्यकताओं की होगी पूर्ति

एन चंद्रशेखरन के अनुसार टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स का लाभ कई सेक्टर को मिलेगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स ऑटोमोटिव, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता और मेडिकल के साथ कई और सेक्टर की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

एन चन्द्रशेखरन ने कहा कि

भारत में कई सेक्टर है जिसमें चिप्स की आवश्यकता है। जाहिर है हम पहले दिन सभी फॉर्म फैक्टर का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम धीरे-धीरे सभी सेक्टर की सर्विस देंगे।

उन्होंने जानकारी दी कि टाटा का चिप प्लांट 28 नैनोमीटर (एनएम) से 110 नैनोमीटर नोड्स में वेफर्स का प्रोडक्शन करने में सक्षम है। स्मार्टफोन, टैबलेट आदि जैसे हाई-टेक गैजेट्स के लिए मुख्य रूप से 3 एनएम, 7 एनएम और 14 एनएम जैसे छोटे नोड्स में चिप्स की आवश्यकता होती है।

वह आगे कहते हैं कि इन प्लांट से बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी। वह कहते हैं कि हम असम में कम से कम 20,000- 22,000 नौकरियों जनरेट होने की संभावना है। हालांकि, इसमें समय लगेगा।

चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी चिप उत्पादन की समयसीमा में तेजी ला रही है।

आम तौर पर सेमीकंडक्टर संयंत्र में लगभग 4 साल लगता हैं। हमारा लक्ष्य कैलेंडर वर्ष 2026 में चिप्स का प्रोडक्शन करना है। उम्मीद है इस वर्ष के उत्तरार्ध में असम में यह काम पहले किया जा सकता है। हम असम में 2025 के अंत में भी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं।

Adidas को कई सालों में पहली बार हुआ भारी नुकसान, Kanye West से करार तोड़ना पड़ा महंगा

परिवहन विशेष न्यूज

Adidas के लिए वर्ष 2023 के नतीजे निराशाजनक रहे हैं। कान्ये वेस्ट से 2022 के अंत में अपना करार खत्म करना कंपनी के लिए भारी नुकसान वाला रहा। कंपनी ने बताया कि उसे 2023 में 75 मिलियन यूरो (करीब 82 मिलियन डॉलर) का घाटा हुआ। इससे पहले कंपनी ने 612 मिलियन यूरो का मुनाफा कमाया था। यह पहला मौका है जब कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है।

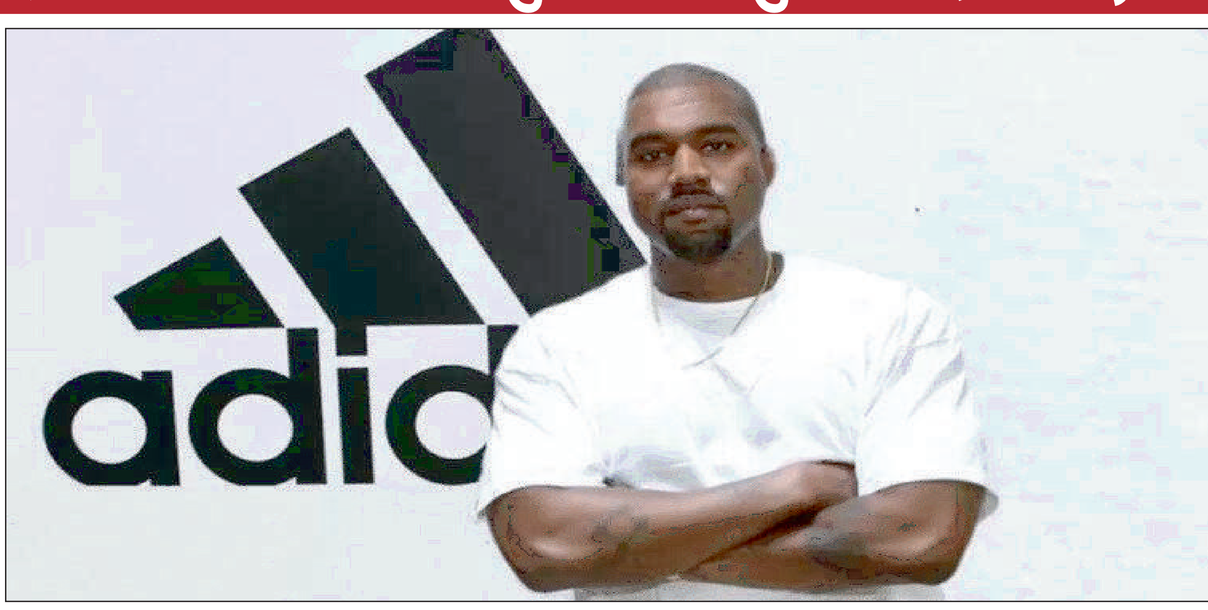

जर्मनी। स्पोर्ट्स वेयर बनाने वाली कंपनी Adidas को 2023 में भारी नुकसान हुआ है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट के साथ करार खत्म करने से उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि, कंपनी ने यह भी बताया कि वह तेजी से नुकसान की भरपाई कर रही है।

साल 2022 में कान्ये वेस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यहूदी विरोधी पोस्ट शेयर किए थे, जिसके बाद जर्मन कंपनी Adidas ने कान्ये वेस्ट के साथ अपना करार खत्म कर दिया था।

75 मिलियन यूरो का नुकसान

Adidas और कान्ये वेस्ट ने मिलकर यीजी ट्रेनर्स (Yeezy trainers) शूज की ब्लॉकबस्टर लाइन तैयार की थी। इस करार के खत्म होने के साथ कंपनी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब कंपनी इन शूज का बड़ा स्टॉक बेच नहीं पाई। इससे उसके राजस्व को भारी घाटा पहुंचा।

Adidas ने बताया कि वर्ष 2023 में उसे 75 मिलियन यूरो (करीब 82 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ है। कई सालों में यह पहला मौका है जब कंपनी नुकसान में रही है। इससे पहले कंपनी ने 612 मिलियन यूरो का मुनाफा कमाया था।

कंपनी का फ्यूचर प्लान

कान्ये वेस्ट के साथ करार खत्म हो जाने के बाद Adidas ने शीर्ष नेतृत्व में भी बदलाव किया। प्रतिद्वंद्वी Puma से Bjorn Gulden को बतौर सीईओ नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि भले ही नतीजे अच्छे नहीं हैं लेकिन बिजनेस को बदलने में वक्त लगेगाा। उन्होंने आगे कहा कि 2023 के नतीजे उतने बुरे नहीं थे जितनी पहले आशंका थी, और 2025 तक हम पहले बेहतर और हमें 2026 तक वास्तव में स्वस्थ कंपनी होना चाहिए।

कंपनी का राजस्व 5 प्रतिशत गिरकर 21.4 बिलियन यूरो हो गया है। यीजी जूतों की बिक्री बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका में हुआ है। हालांकि कंपनी धीरे धीरे यीजी शूज की बिक्री शुरू कर रही है।

कंपनी यीजी जूतों को लागत मूल्य पर बेचेगी। अनुमान है कि इससे करीब 250 मिलियन यूरो का राजस्व मिलेगा। कंपनी के लिए चीन से भी राहत की खबर आई है, जहां उसकी बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई है।

फटाफट लाभ के लिए F&O में खुदरा निवेशकों का आना चिंताजनक: नागेश्वरन

सीईए वी अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि वह तत्काल लाभ की तलाश में जोखिम भरे वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में खुदरा निवेशकों की भागीदारी से चिंतित हैं। एक सम्मेलन में नागेश्वरन ने कहा कि टिकाऊ पूंजी निर्माण और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा निवेशकों के नजरिये में जल्दबाजी का होना है और देश इस समय इस प्रवृति की चपेट में है।

मुंबई: मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि वह तत्काल लाभ की तलाश में जोखिम भरे वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में खुदरा निवेशकों की भागीदारी से चिंतित' हैं।

बाजार नियामक सेबी और NISM की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन में नागेश्वरन ने कहा कि टिकाऊ पूंजी निर्माण और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा निवेशकों के नजरिये में जल्दबाजी का होना है और देश इस समय इस प्रवृत्ति की चपेट में है।

F&O कारोबार में शानदार वृद्धि

उन्होंने कहा कि अब भी लोग एफएंडओ कारोबार की मात्रा में शानदार वृद्धि का जिक्र कर रहे हैं जबकि खुद सेबी के अध्ययन बताते हैं कि जोखिम वाले इस खंड में 90 प्रतिशत कारोबार में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है।

नागेश्वरन ने कहा कि एफएंडओ खंड में कारोबार के पीछे त्वरित लाभ की मंशा होती है, लेकिन छोटे निवेशकों का बढ़ता जोखिम चिंता की बात है क्योंकि बार-बार तेजी और मंदी के चक्र से नहीं गुजरना चाहता है।

जीडीपी में बढ़ोतरी

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। यह लगातार तीसरा साल होगा जब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सात प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को पर्याप्त पूंजी देने की भी आवश्यकता है और अगर बैंकों को पूंजी प्राप्त करनी है तो बैंकों के कॉर्पोरेट स्वामित्व की अनुमति देनी होगी।

बैंकों के कॉर्पोरेट स्वामित्व पर चर्चा करना भी वर्जित क्यों है? तथ्य यह है कि कॉर्पोरेट घरानों को बैंकों के लाइसेंस देने के विचार की चर्चा मात्र से ही इस तरह की प्रतिक्रिया या हंगामा पैदा हो जाता है, जो वास्तव में कॉर्पोरेट्स के लिए भी चिंतन का कारण है।

दिल्ली में किसानों की महापंचायत, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी; इन मार्गों पर जाने से बचें

ट्रैफिक एडवाइजरी (Traffic Advisory) के अनुसार, गुरुवार को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सामान्य यातायात की आवाजाही नियंत्रित रहेगी।

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार को किसानों की महापंचायत होने जा रही है। राजधानी में आसपास के राज्यों से किसान पहुंचने वाले हैं जिस कारण कई मार्गों पर डाइवर्जन रहेगा। इस वजह से पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। लोगों को एडवाजरी फॉलो करने की सलाह दी गई है। गुरुवार को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सामान्य यातायात की आवाजाही नियंत्रित रहेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार को किसानों की महापंचायत (Farmers Mahapanchayat) होने जा रही है। राजधानी में आसपास के राज्यों से किसान पहुंचने वाले हैं, जिस कारण कई मार्गों पर डाइवर्जन रहेगा। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) लोगों को एडवाजरी फॉलो करने की सलाह दी गई है।

इन मार्गों पर आवाजाही नियंत्रित

ट्रैफिक एडवाइजरी (Traffic Advisory) के अनुसार, गुरुवार को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सामान्य यातायात की आवाजाही नियंत्रित रहेगी। इनमें जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बाराखंभा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग, आसफ अली रोड, जय सिंह रोड, स्वामी विवेकानंद मार्ग, संसद मार्ग, नेता जी सुभाष मार्ग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, मिंटो रोड, अशोक रोड, महाराजा रणजीत सिंह पर फ्लाईओवर, कनॉट सर्कस, भवभूति मार्ग, डीडीयू मार्ग और चमन लाल मार्ग शामिल हैं।

इन जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्जन

सुबह 6 बजे से दिल्ली गेट, मीर दर्द चौक, अजमेरी गेट चौक, गुरु नानक चौक, कमला मार्केट रोड, पहाड़गंज चौक, गोल चक्कर झंडेवालान, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर बाराखंभा रोड से गुरु नानक चौक, टॉल्स्टॉय मार्ग क्रॉसिंग, केजी मार्ग क्रॉसिंग और राउंडअबाउट जीपीओ, जनपथ रोड तक ट्रैफिक डायवर्जन लगाया जा सकता है।

लोगों को ट्रैफिक पुलिस की सलाह

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया कि लोग इन मार्गों से बचकर चलें, या फिर बाईपास का उपयोग करेंष वो सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो का प्रयोग करने का अनुरोध किया है।

ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे परिवर्तित मार्गों से सड़क यात्रा की योजना बनाते समय पर्याप्त समय रखें। जो लोग आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे की ओर जा रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय के साथ सावधानीपूर्वक अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

ज़िला कलेक्टर ने किया ज़िले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अधिकारियो तथा कार्मिको की मौजूदगी का औचक निरीक्षण

परिवहन विशेष न्यूज

शाहपुरा नवगठित ज़िले शाहपुरा में कार्यालय निर्धारित समय से पहुँचने के अनुशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को प्रातः 9.30 से 10.00 बजे के बीच ज़िला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने ज़िले में संचालित हो रहे विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अधिकारियो तथा कार्मिको जी उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया।

ज़िला कलेक्टर शेखावत ने ज़िले के पंचायत समिति कार्यालय , सूचना एवं प्रोद्योगिकी कार्यालय तथा आई सी डी एस कार्यालय का निरीक्षण किया। ज़िला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान ज़िले के पंचायत समिति कार्यालय का 01 कार्मिक अनुपस्थित पाया गया । निरीक्षण के दौरान ज़िला कलेक्टर शेखावत ने पंचायत समिति कार्यालय के प्रत्येक सेक्शन की कार्यप्रणाली का मुआइना किया तथा सभी लंबित प्रकरणों के समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियो तथा कर्मचारियो को निर्देशित किया।

ज़िला कलेक्टर शेखावत ने बताया की कार्य संचालन में समयबद्धता के अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा इस प्रकार के आकस्मिक निरीक्षण भविष्य में भी किए जाएँगे तथा लगातार अधिकारियो एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय पर कार्यालय में अनुपस्थित पाये जाने पर सख़्त कार्रेवाई की जाएगी। ज़िला कलेक्टर शेखावत ने ज़िले के सभी संबंधित एसडीओ तथा तहसीलदारो को भी इस प्रकार का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया जिस से ज़िले के समस्त ब्लॉको तथा तहसीलों में भी अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।

दिल्ली मेट्रो फेज-4 को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 8400 करोड़ की लागत से बनेंगे दो कॉरिडोर

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के निर्माण को मंजूरी दे दी है। कुल 8399 करोड़ रुपये की लागत पर इस परियोजना के तहत दो कॉरिडोर– लाजपत नगर से साकेत जी–ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक का निर्माण किया जाएगा। दोनों कॉरिडोर में कुल 18 स्टेशनों का निर्माण होगा और यह मार्च 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 8,399 करोड़ रुपये की लागत पर दिल्ली मेट्रो चरण-IV को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के तहत दो कॉरिडोर- लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक का निर्माण किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'आज दो नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, जिस पर 8400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक करीब 8.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन होगी। इसमें आठ स्टेशन होंगे। दूसरी इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक करीब 12.4 किलोमीटर की मेट्रो लाइन होगी। यह मार्च 2029 तक पूरी हो जाएगी।'

लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर

1. यह कॉरिडोर सिल्वर, मैजेंटा, पिंक और वॉयलेट लाइन को कनेक्ट करेगा।
2. यह पूरी तरह एलिवेटेड होगा और इसमें कुल 8 स्टेशन होंगे।

इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर

1. ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन होगा
2. इसमें 11.34 किलोमीटर अंडरग्राउंड लाइन जबकि 1.02 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। इसमें 10 स्टेशन होंगे।
3. इसमें रेड, येलो, एयरपोर्ट लाइन, मैजेंटा, वॉयलेट और ब्लू लाइन के लिए इंटरचेंज किया जा सकेगा।
4. इस कॉरिडोर के जरिए बहादुरगढ़ तक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी।

नए कॉरिडोर में प्रस्तावित स्टेशन

लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक कॉरिडोर के स्टेशनः लाजपत नगर, एंड्रयूज गंज, ग्रेटर कैलाश - 1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत जिला केंद्र, पुष्प विहार, साकेत जी - ब्लॉक।

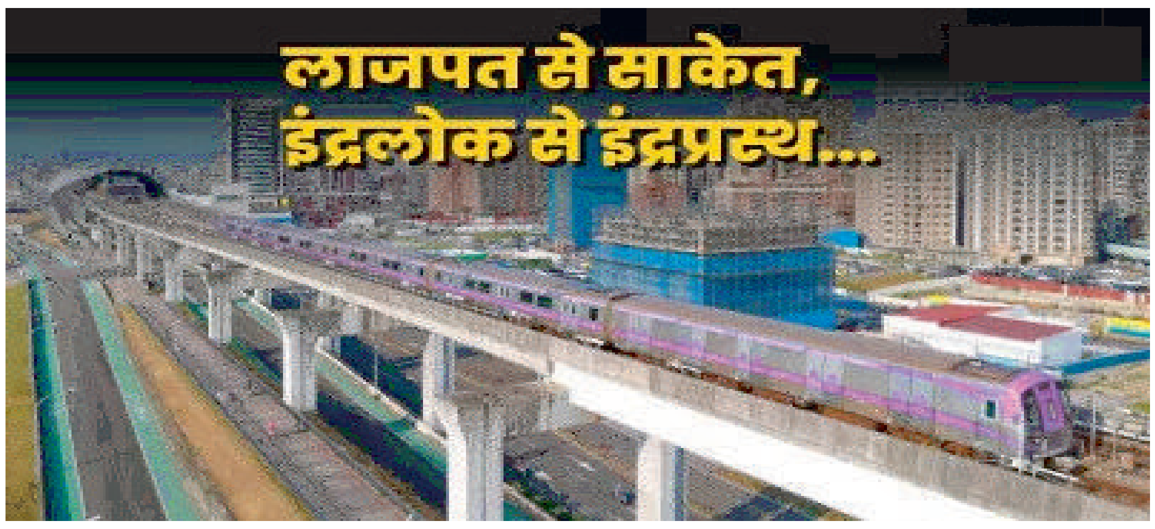

इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के स्टेशनः इंद्रलोक, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, अजमल खान पार्क, नबी करीम, नई दिल्ली, एलएनजेपी अस्पताल, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय, इंद्रप्रस्थ।

दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर प्रोजक्ट

पूरी दिल्ली में मेट्रो का कुल 427 किमी लंबा नेटवर्क है। इसमें 34 किमी का नेटवर्क एनसीआर में भी विस्तृत है। दिल्ली में मेट्रो का दायरा 392.44 किमी तक फैला है।

दिल्ली मेट्रो से रोज 60 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, जिस कारण यह दिल्ली की लाइफ लाइन बन जाती है। दिल्ली मेट्रो अब दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक है।

2019 में, 3 कॉरिडोर एयरोसिटी-तुगलकाबाद, आर.के. आश्रम मार्ग-जनक पुरी पश्चिम और मजलिस पार्क-मौजपुर को लगभग 24,950 करोड़ की लागत से मंजूरी दी गई थी। इन हिस्सों पर निर्माण कार्य चल रहा है और इन्हें वर्ष 2026 तक चालू कर दिया जाएगा।

हरियाणा की तीन सीटों पर भाजपा ने घोषित किए उम्मीदवार

गुरुग्राम/फरीदाबाद। Lok Sabha Chunav 2024: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें हरियाणा की तीन सीटों पर भाजपा (BJP) ने प्रत्याशियों को उतारा है। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी (महेंद्रगढ़) लोकसभा सीट शामिल है। गुरुग्राम से भाजपा ने फिर से राव इंद्रजीत सिंह (Indrajit Singh) पर दांव लगाया है। वह वर्तमान भी इसी सीट से लोकसभा सांसद हैं। वहीं, फरीदाबाद से भी वर्तमान सांसद कृष्ण पाल गुर्जर (Krishna Pal Gurjar) पर भरोसा जताया है और भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। भिवानी (महेंद्रगढ़) सीट से भी चौधरी धर्मवीर सिंह (Dharmveer Singh) उम्मीदवार चुने गए हैं, यह भी वर्तमान सांसद है।

सामाजिक स्तर पर नई चेतना और समाज में जागरूकता लाने के लिए सम्मेलन का आयोजित किया

परिवहन विशेष न्यूज

हैदराबाद। शमशाबाद परिवहन विशेष सीरवी समाज शमशाबाद आई माताजी मंदिर में सामाजिक स्तर पर नई चेतना और समाज में जागरूकता लाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रत्येक महीने की चांदनी बीज महोत्सव रखें समाज में सीरवी समाज भारत में बडेर 700 हर बडेर से नीवल राशि आतीं है ,उसमें से राशि 10% प्रतिशत राशि शिक्षा में देना है एक लड़की या लड़का में एक बडेर किसी भी को पढाई के लिए बडेर का नाम होगा सा नशामुक्ति होना है, और समाज में सोशल मीडिया पर महिलायो एवं बच्चों के लिए बहुत मानसिकता कमजोर कर सकती हैं जैसे इंस्टाग्राम जैसे फेसबुक अन्य सोशल मीडिया एप रहता है कोई बच्चों को बच्चों को बोलते हैं कि आप यह इंस्टाग्राम फेसबुक जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देना है तो बच्चे क्या करते हैं कि वह तनाव में आकर मानसिकता में वह कुछ गलत कदम उठा लेते हैं उसी के लिए उनके माता-पिता को बहुत दुख दर्द होता है और समाज में और निर्णय शिक्षा पर जोर देने का बात रखी गई है समाज में एकता रखने का बात रखी गई थी कई मुख्य उद्देश्य रखे गए थे आने वाले और समाज की मीटिंग में रखी जाएगी सीरवी समाज में बडेर बनाते हैं फीर मंदिर जाने समय नहीं है, मन्दिर खाली एक साल दो बार ही भीड़ रहती है इसलिए समाज में जागरूकता आना जरूरी है मंदिर जाते हैं तो वह पर आरती एवं संस्कृति एवं संस्कार इन बातों कमी नहीं अखिल भारतीय सीरवी महासभा तेलंगाना के प्रान्तिय अध्यक्ष एवं सीरवी समाज शमशाबाद के मुख्य संरक्षक हरजीराम काग अखिल भारतीय सीरवी महासभा तेलंगाना के सचिव सोहनलाल हाम्बड़ उपाध्यक्ष माणक लाल सीरवी सह सचिव गिरधारी लाल काग एवं सीरवी समाज के विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के रूप में पधारने वालों मे कोरूमला बडेर से अध्यक्ष कालुराम काग सचिव डायाराम लचेटा करमन घाट बडेर के अध्यक्ष श्री प्रकाश आगलेचा ,श्री पुखराज चोयल,पूर्व अध्यक्ष हंसाराम आगलेचा , पूर्व सचिव नेमाराम काग,संगारेड्डी बडेर से अध्यक्ष रुगाराम परिहारिया, अन्य प्रतिनिधियों में चंदा राम परिहारिया, लिखमाराम सानपुरा, मल्लापुर बडेर से अध्यक्ष बाबूलाल मुलेवा सचिव तुलछाराम सिन्दडा एवं ओंकारराम हाम्बड, एलबी नगर बडेर से अध्यक्ष जगदीश प्रसाद काग ,सचिव श प्रकाश सेपटा, मानिकोंडा से सचिव मोतीलाल मादावत, शाषदनगर से अध्यक्ष कैलाश जी बर्फा,सचिव भंवर लाल सैणचा, वीरमगुड़ा से उपाध्यक्ष राकेश जी चोयल, सचिव मोहनलाल भायल, जनगांव से अध्यक्ष किशन लाल हाम्बड, सचिव पुनाराम हाम्बड एवं लादूराम काग, जिडिमेटला बडेर से अध्यक्ष मांगीलाल काग एवं सचिव नारायण लाल बर्फा, श्री आईजी सेवा संघ के अध्यक्ष भगाराम मुलेवा, आईजी क्षत्रिय विकास सेवा समिति के महासचिव एवं भारत टाइम्स के रिपोर्टर जगदीश सोलंकी राजस्थान से पधारने वालों में अतिथि के रूप में सोजत सीरवी छात्रावास की उपाध्यक्ष कन्हैयालाल गहलोत एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा संघ के सेवानिवृत जिला स्तरीय अधिकारी अगरा राम चोयल, पंचायत समिति सदस्य देवली कला से गौरी देवी काग एवं कर्नाटक राज्य के दावणगिरी से पधारने वालों में जोराराम काग एवं पुनाराम पंवार अन्य अतिथियों के रूप में भाग लेने वालों में ब्रह्म ऋषि डॉक्टर अनिल कुमार जोशी(निखिल चेतना केंद्र), कौत्तागुडा के सरपंच मल्ला रेड्डी , जिला सचिव करनागुड़ा नरसिम्हा रेड्डी, बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष सोमराज वेंकटेश, कन्दकूर के सरपंच मनम जयन्द्र, सीरवी समाज शमशाबाद के सचिव महोदय के पिता मालाराम जी पंवार, सिखवाल समाज के श्री राम प्रकाश ओझा, रवि कुमार (प्राचार्य), एडवोकेट श्रीनिवास रेड्डी एवं अशोक कुमार, एडवोकेट मुरली सर अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष धर्माराम ढाका, जगदीश जाट, बाबूलाल जाट(कोत्तुर) दुदाराम जाट, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष भाकर राम कुमावत, सीरवी समाज शमशाबाद के तीनों समितियां के अध्यक्षमय सदस्यों ने भाग लिया जिसमें समाज के अध्यक्ष श्री आसाराम गहलोत,उपाध्यक्ष चेलाराम काग,बाबुलाल पंवार, सचिव भोलाराम पंवार , सह-सचिव नरेश परिहार, कोषाध्यक्ष राजूराम परिहार, शिक्षा समिति के अध्यक्ष केसाराम काग, उपाध्यक्ष भैराराम परिहारिया, मांगीलाल सोलंकी, सचिव भीकाराम काग, खेल मंत्री पुखराज पंवार ,मीडिया प्रभारी हेमंत काग, महिला मंडल समिति के अध्यक्ष पारी देवी काग, उपाध्यक्ष संतोष देवी परिहार, गंगादेवी काग, सीरवी समाज शमशाबाद के अन्य गणमान्य में पूर्व सचिव एवं सलाहकार सदस्य भूराराम परिहार, पूर्व कोषाध्यक्ष एवं सलाहकार सदस्य श्री हरिराम परिहारिया, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मल्लाराम पंवार, पूर्व सहसचिव एवं सलाहकार सदस्य जगदीश काग उपस्थित रहे।

फेम जिला आगरा के जिलाध्यक्ष घोषित हुए वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

आगरा। आज फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल की एक आवश्यक बैठक फेम के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोबती की अध्यक्षता में खंदारी स्थित होटल सी.पी.पैलेस में आहूत हुई।

बैठक में फेम की आगामी कार्ययोजना पर चर्चा से पूर्व सर्वप्रथम भूपेंद्र सिंह सोबती ने वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना को फेम का ज़िला अध्यक्ष घोषित किया एवं शीघ्र ही आपसी विचार विमर्श कर कार्यकारिणी गठन करने के लिए निर्देशित किया।

इस अवसर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेश खुराना ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार अप्रेल के प्रथम सप्ताह तक फेम की कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही शहर में आगरा शहर के सभी वर्गों के व्यापारियों को फेम का सदस्य बनाया जाएगा एवं फेम व्यापारियों की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहेगा।

इस दौरान इस बैठक में शिवम गर्ग, धर्मवीर कौशिक, दीप बघेल, अनुज सिंघल, अमन कुलकरिष्ठ, संतोष सिंह, चंद्रभान, मनोज शर्मा, राजपाल राजपूत, नीतेश उपाध्याय, लिली गोयल, अमित बजाज, पूरण चंद्र वर्मा, जीतेश कुमार, प्रेम शर्मा, गौरव जैन, मनीश कुमार, मुकेश निर्वाणिया, मनोज कुमार, रूपेश कुमार, मनोज खंडेलवाल, नागेंद्र शर्मा उपस्तिथ रहे एवं सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

भीलवाड़ा विधायक कोठारी ने जिला कारागृह का किया औचक निरीक्षण

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। विधायक अशोक कोठारी अचानक दिन को 12:15 बजे अजमेर पुलिया के पास जिला जेल परिसर पहुंचे। वहां जेल अधीक्षक भैरू सिंह राठौड़ व डिप्टी जेलर हीरा लाल मिले। विधायक कोठारी ने नियमानुसार रजिस्टर में नाम, हस्ताक्षर आदि औपचारिकता पूरी कर काउंटर पर मोबाइल जमा करा कर परिसर में प्रवेश किया।

मीडिया प्रभारी सत्यम शर्मा ने बताया कि भीलवाड़ा विधायक सर्वप्रथम कैदियों की भोजनशाला पहुंचे, वहां रसद सामग्री दाल - सब्जियां, आटा, नमक को देखा तथा अभी प्रातः में जो भोजन दिया गया उसमें चपाती, दाल - सब्जी व खिचड़ी को स्वयं ने चखा तथा रोटी की क्वालिटी को और उत्तम बनाने के लिए मशीन का उपयोग करने को कहा, जिससे कैदियों को चपाती फूली हुई व एक जैसी उपलब्ध हो पाए। तत्पश्चात सफाई व्यवस्था व पीने के पानी की व्यवस्था देखी। वहां जेल अधीक्षक ने कहा कैदियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था अभी नहीं है, तो विधायक महोदय ने एक-दो दिन में ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

डिप्टी जेलर हीरालाल ने बताया जेल को सीवरेज से नहीं जोड़ा गया है तथा पीछे परिसर में झाड़ियां व बबूल हैं जिससे सफाई पूरी तरह नहीं हो पाती है, तो विधायक महोदय ने अविलंब परिषद आयुक्त को फोन कर निर्देश दिए कि यहां जेसीबी भेज कर तुरंत समाधान करें तथा सीवरेज के लिए भी शीघ्र ही व्यवस्था करवाने की कहा। तत्पश्चात कैदियों के ग्राउंड परेड के अंतर्गत कैदियों से सीधी बातचीत की व परिजनों से मुलाकात के समय व परिसर का भी अवलोकन किया। कोठारी ने कैदियों को अपने विचार रखते हुए समझाया, ज्ञात - अज्ञात, आवेश में आकर इंसान अपराध कर बैठता है या अपराध हो जाता है या पूर्व जन्म का कोई कर्म होता है जिससे सजा भुगतान पड़ती है, परंतु उस भूल को हम सुधार सकते हैं। प्रायश्चित, प्रार्थना, सेवा कर आप जीवन का रास्ता परिवर्तित कर सकते हैं। प्रार्थना व ईश्वर के नाम स्मरण से अपराधी का अपराध कम हो जाता है व भविष्य में सत्कर्म करते हुए परिवार, समाज का आदर्श बन सकता है। कुछ अच्छी पुस्तक भी पढ़ें, सभी के प्रति प्रेम का भाव रखें, समय परिवर्तित होता है, खराब समय निकल जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। जीवन में कभी कुंठित नहीं रहना चाहिए। इस मौके पर भाजपा पूर्व जिला महामंत्री बाबूलाल टाक व शंभू लाल वैष्णव भी साथ थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी–18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए–4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली– 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023